

### सहकारी और औद्योगिक क्षेत्र का पुनरुद्धार

महाराष्ट्र सरकार ने धुले स्थित 'जवाहर शेतकरी सहकारी कताई मिल' को फिर से चालू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मिल के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय मदद प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को भेजा जाएगा। यह कदम स्थानीय रोजगार और कपड़ा उद्योग के लिए सजीवनी साबित होगा।

### लंबित भुगतानों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

टेकेदारों के लंबित भुगतानों के निपटान के लिए टी-रीडीएस प्लेटफॉर्म शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा लोक निर्माण विभाग से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम टेकेदार-उद्यमियों के लिए होगी। राज्य सरकार ने धुले में जवाहर शेतकरी सहकारी कताई मिल को पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया है। इस संबंध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली को एक सिफारिश भेजी जाएगी।

# DBD

## दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिसांसिबिलिटी है

### 'पीएम सेतु' योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू

बैठक में यह निर्णय किया गया कि 'पीएम सेतु' योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू की जाएगी। इससे इच्छुक युवाओं को राहत मिलेगी। पहले चरण में इसे नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे जिलों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। अगले चरण में राज्य के अन्य संस्थानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पीएम सेतु (प्रधानमंत्री कोशल विकास एवं रोजगार क्षमता उन्नयन योजना) से उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

### मुंबई एयरपोर्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन 8 को कैबिनेट से मंजूरी



### जनहित के फैसले

# फडणवीस सरकार ने लगाई फैसलों की झड़ी

## 22,000 करोड़ की 'मेट्रो लाइन 8' सहित कई प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी



### शत्रु संपत्ति स्टेम्प ड्यूटी माफी

कैबिनेट ने 'शत्रु संपत्ति' की खरीद-बिक्री को आसान बनाने के लिए एक और अहम फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार के कस्टोडियन ऑफ एनिमि प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया (सीईपीआई) द्वारा बेची जाने वाली शत्रु संपत्तियों के पहले रजिस्ट्रेशन पर मुद्रांक शुल्क (स्टैप ड्यूटी) पूरी तरह माफ कर दी गई है। युद्ध के दौरान जो लोग भारत छोड़कर शत्रु देशों में बस गए, उनकी संपत्तियों को 'शत्रु संपत्ति' कहा जाता है। राज्य में ऐसी कुल 428 संपत्तियां हैं, जिनमें सबसे अधिक मुंबई उपनगर (177) और ठाणे (86), पालघर में 77 और मुंबई में 62 संपत्तियां शामिल हैं। अवसर इन संपत्तियों की नीलामी में खरीदारों की रुचि कम देखी गई है। सरकार का मानना है कि स्टैप ड्यूटी माफ होने से संपत्तियों की लागत कम होगी और खरीदार आकर्षित होंगे।

### डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में रोजगार, राजस्व और उद्योग विभाग से जुड़े 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। युवाओं के रोजगार, टेकेदारों के बकाया बिल, सरकारी जमीन के पट्टे की अवधि जैसे विभिन्न मुद्दों पर बैठक में गहन चर्चा हुई और इस क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के कारण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अब बढ़ेंगे। बैठक में ITI में पीएम सेतु योजना शुरू करने का निर्णय किया गया। साथ ही, महाराष्ट्र सरकार ने इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने शत्रु संपत्ति की खरीद-बिक्री पर स्टैप शुल्क माफ करने का फैसला किया है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए क्योंकि वह अभी सतारा जिले में अपने घर पर हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कैबिनेट मीटिंग के बाद साफ किया कि वह वहां किसी काम से गए थे। उन्होंने महायुति में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया।

### सरकारी जमीनों की लीज अब 49 साल

मंत्रिमंडल ने सरकारी जमीन की लीज अवधि बढ़ाने का भी नीतिगत निर्णय लिया है। अब 30 वर्ष के लीज पर दी गई जमीन की अवधि बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों, महामंडलों, बोर्डों और प्राधिकरणों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी जमीनों अब व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं को लंबी अवधि के पट्टे पर दी जा सकेगी। महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 और महाराष्ट्र भू-राजस्व (सरकारी जमीन का निपटान) नियम,

1971 के तहत विभिन्न कारणों से सरकारी जमीन 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाती थी। नए निर्णय के अनुसार, अब इस अवधि को बढ़ाकर पहले चरण में अधिकतम 49 वर्ष किया जा सकेगा। नए फैसले के अनुसार, अब यह जमीनें शुरूआत में अधिकतम 49 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जा सकेगी। लेकिन यदि पट्टाधारक ने किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, तो संबंधित विभाग आवश्यकतानुसार इस पट्टे का नवीनीकरण कर सकेगा। अर्थात् नियमों

का पालन करने पर कुल अवधि 98 वर्ष तक जमीन का पट्टा मिल सकता है। इस निर्णय से विभिन्न महामंडलों, मंडलों और प्राधिकरणों को अपनी आय बढ़ाने और व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जिला कलेक्टर कार्यालय इन जमीनों के किराए और नवीनीकरण पर कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही पट्टे की जमीन के किराए (भूमि भाड़ा) में निश्चित अंतराल पर वृद्धि और किराए की नियमित वसूली व जिला प्रशासन द्वारा निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

### मुंबई-नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच सफर होगा आसान स्टेशन और जमीन अधिग्रहण का विवरण

#### डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन 8 के कनेक्शन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मेट्रो लाइन की कुल लंबाई 35 किलोमीटर होगी, जिसमें 9.25 किलोमीटर अंडरग्राउंड और 24.636 किलोमीटर एलिवेटेड होगी। कुल 20 स्टेशन होंगे, जिनमें से 6 अंडरग्राउंड और 14 एलिवेटेड होंगे।

मेट्रो लाइन का मार्ग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 स्टेशन से घाटकोपर ईस्ट तक अंडरग्राउंड होगा। घाटकोपर वेस्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 तक एलिवेटेड स्टेशन होंगे। दो स्टेशनों के बीच औसत दूरी 1.9 किलोमीटर तय की गई है। इसके लिए 30.7 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने की आवश्यकता है और जमीन अधिग्रहण की अनुमानित लागत 388 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 22,862 करोड़ रुपये बताई गई है।

### वित्तीय योगदान और प्रोजेक्ट समय सीमा

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में राज्य और केंद्र सरकार दोनों 20 प्रतिशत वार्यबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में योगदान देंगे। शेष 60 प्रतिशत राशि मेट्रो निर्माण करने वाली निजी कंपनी द्वारा लाई जाएगी। प्रोजेक्ट पूरा करने का तय समय पांच साल है, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस चाहते हैं कि इसे केवल साढ़े तीन साल में पूरा किया जाए।

### भारत-ईयू मुक्त व्यापार सौदा : अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट, सस्ता होगा सामान

# 18 साल बाद मदर ऑफ ऑल डीलस डन

इम्पोर्टेड लजरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10%, प्रीमियम शराब पर 150% की जगह 20% टैक्स एजेंसी | नई दिल्ली



दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आज एक नया अध्याय खुल गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अब पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। यह डील न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक ताकत को दिखाती है, बल्कि कारोबार, निवेश और रोजगार के नए रास्ते भी खोलती है।

### सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता

भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच अब तक के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोहर लगा दी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने अपना सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया, यूरोपीय संघ के साथ यह मुक्त व्यापार समझौता साझा समृद्धि का नया खाका है। भारत-यूरोपीय संघ सहयोग वैश्विक हित में एक साझेदारी, यह एफटीए समुद्री क्षेत्र और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। अमेरिका की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक माहौल में उथल-पुथल मची हुई है, भारत-ईयू विश्व व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करेगा। इस डील को लेकर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष फॉन्टिनी कोस्टा ने कहा, शिखर सम्मेलन ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत और यूरोपीय संघ विश्वसनीय साझेदार के रूप में एक साथ खड़े हैं। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दो अरब लोगों के बाजार के लिए अब तक का सबसे महत्वकांक्षी समझौता है।

### भारत की अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ

यूरोपीय संघ (EU) के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील से भारत को न्याय, निवेश, रोजगार और वैश्विक रणनीतिक ताकत-चारों मोर्चों पर बड़ा फायदा होने वाला है। इस समझौते के तहत भारत के 9,000 से अधिक उत्पादों पर टैरिफ कम या समाप्त होंगे, जिससे टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार EU तक सीधी पहुंच मिलेगी। MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नए ऑर्डर और रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं किसानों और मछुआरों को कृषि व समुद्री उत्पादों के बेहतर दाम और स्थिर मांग का लाभ होगा। IT, फिनेटेक, हेल्थ और एजुकेशन समेत सर्विस सेक्टर को यूरोप के 144 सब-सेक्टर में आराम पंटी मिलेगी, जिससे छात्रों और रिकवर्ड प्रोफेशनल्स के लिए वीजा अवसर भी बेहतर होंगे। इसके साथ ही EU कंपनियों के निवेश से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर, EV, ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस जैसे हाई-टेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। आम उपभोक्ताओं को भी यूरोपीय कारों, मेडिकल उपकरणों और अन्य उत्पादों के सस्ते होने का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह डील भारत को ग्लोबल सप्लाय चेन हब बनाने, विदेशी दबावों के विकल्प तैयार करने और स्वतंत्र व्यापार नीति को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।

### अमेरिका को नहीं रास आई यह डील

यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच यह डील अमेरिका को नहीं रास आ रही है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बसेंट ने एक दिन पहले ही कहा था कि यूरोपीय देश अपने ही खिलाफ युद्ध की फंडिंग करने जा रहा है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन को धोखेबाज तक कहा। दरअसल अमेरिका ने रूस से तेल आयात के नाम पर भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हो पाई और ईयू वाली डील फाइनल हो गई।

### महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षण

## महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

### नाए सिरे से जांच की उठी मांग



#### एजेंसी | नई दिल्ली/मुंबई

महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में ओबीसी (OBC) आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीघ्र अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें 2022 की 'न्यायमूर्ति बंधिया आयोग' की रिपोर्ट और उससे जुड़े सभी फैसलों को रद्द करने की मांग की गई है।

### 'यूथ फॉर इक्वालिटी' ने दी चुनौती

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सुर्यकांत की पीठ ने 'यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन' द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि बंधिया आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया जाए क्योंकि उसने आरक्षण देने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है।

### नया आयोग बनाने की मांग

याचिका में केवल पुरानी रिपोर्ट को रद्द करने की ही बात नहीं कही गई है, बल्कि एक वैकल्पिक समाधान भी सुझाया गया है। फाउंडेशन ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार को एक 'नया आयोग' गठित करने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नया आयोग सभी स्थानीय निकायों में 'राजनीतिक पिछड़ेपन' का अध्ययन करे और केवल 'टोस डेटा' के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट सौंपे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि न्यायमूर्ति बंधिया आयोग को आरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं था। आरोप लगाया गया है कि आयोग ने गलत तरीके से और बिना पर्याप्त आधार के आरक्षण की सिफारिश की। वहीं, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पहले से ही याचिकाएं लंबित हैं, अब इस नई याचिका को भी उनके साथ देखा जाएगा।

### प्लैबैक गानों में सुनाई नहीं पड़ेगी अरिजीत की आवाज

मुंबई | आइकॉनिक प्लैबैक सिंगर अरिजीत ने प्लैबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अरिजीत की वो मीठी सुरीली आवाज अब आपको प्लैबैक गानों में सुनाई नहीं पड़ेगी। अरिजीत सिंह ने अपने रिटायरमेंट की खबर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को दी। सिंगर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'हैलो, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने सालों तक मेरे गाने सुनकर मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे यह पेलान करते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं प्लैबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया आइडनमेंट नहीं लूंगा।'

### आज से बजट सत्र का आगाज

सर्वदलीय बैठक में 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल सरकार का VB-G RAM-G कानून पर चर्चा से इनकार एजेंसी | नई दिल्ली



### क्या बोले किरेन रिजिजू?

ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विधायी एजेंडा शेयर नहीं करने के आरोप पर कहा कि राष्ट्रपति के अधिभाषण के बाद सरकार अधना एजेंडा शेयर करती है। विपक्ष को बोलने की आजादी है, लेकिन सुनना भी जरूरी है। उन्होंने मन्त्रेया की जगह लाए गए VB-G RAM-G कानून पर चर्चा की मांग खारिज कर दी।

मीटिंग के बाद विपक्षी सांसदों की प्रतिक्रिया शिवसेना (UBT) MP अरविंद सावंत की सभी ने अपने-अपने राज्यों के हिसाब से अपनी मांगें रखी हैं। प्रदूषण, SIR, बढ़ती बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं और भी बहुत कुछ। वहीं समाजवादी पार्टी MP राम गोपाल यादव कि इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। बजट उन्हीं के लिए है जिनके पास संपत्ति है।

### यूजीसी नए नियमों पर 'सवर्ण' आक्रोश, सरकार बोली- कोई भेदभाव नहीं होगा

# देशभर में प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

#### एजेंसी | नई दिल्ली/लखनऊ

यूनियनसिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा जारी 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026' के खिलाफ देशभर में जनरल कैटेगरी (सामान्य वर्ग) के छात्रों और संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित UGC मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की है।



### महाराष्ट्र-दिल्ली से यूपी तक उखाल, सांसदों को भेजी वृद्धियां

विरोध की आग उत्तर प्रदेश के कई शहरों तक फैल गई है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और सीतापुर में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडेय ने अपना विरोध जताते हुए सवर्ण सांसदों को वृद्धियां भेजीं।

### अधिकारी का इस्तीफा और कुमार विश्वास का तंज

इस मुद्दे पर प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन नए नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो एक बड़ी घटना मानी जा रही है। वहीं, प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर लिखा: 'चाहे तिल लो या ताल लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं भमंगा 'सवर्ण' हूँ... मेरा रांछा-रांछा उखाड़ लो राजा।'

### सरकार की सफाई और कोर्ट में चुनौती

विरोध बढ़ता देख केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून का गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन नियमों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए दंड को हटाए जाने पर मैं चिंता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इससे छात्रों और शिक्षकों के उत्पीड़न की संभावना बढ़ सकती है। अनिवार्य समानता समितियों में 'सामान्य वर्ग' के प्रतिनिधित्व को बाहर रखना उचित नहीं है।  
- नितेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष, अ. भा. ब्राम्हण जनकल्याण समिति

# ठाणे-बेलापुर रोड पर तुर्भे स्टोर ब्रिज की राह साफ

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

ठाणे-बेलापुर रोड पर स्थित तुर्भे स्टोर के पास प्रस्तावित ब्रिज निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बनी भूमिगत पाइपलाइन को हटाने का काम आखिरकार शुरू हो गया है। आचार संहिता समाप्त होते ही संबंधित विभाग ने पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य चालू कर दिया है। इसके पूरा होते ही वर्षों से अटके इस बहुप्रतीक्षित ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। यह ब्रिज पिछले करीब 20 वर्षों से क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग रहा है। इसके पूरा होने से तुर्भे एमआईडीसी और आसपास के इलाकों में रहने वाले 25 हजार से अधिक नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और ठाणे-बेलापुर रोड पर लगने वाले भीषण ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी।

## पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम शुरू, वर्षों बाद आगे बढ़ेगा बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट



### एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप के बाद बदली तस्वीर

वर्ष 2020 में तत्कालीन पालकमंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए ब्रिज का काम जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद काम की शुरुआत तो हुई, लेकिन अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए डिजाइन को स्थानीय नागरिकों से छिपाया गया। जब यह डिजाइन सामने आया, तो नागरिकों ने तीव्र विरोध किया। विरोध के बाद आखिरकार डिजाइन में बदलाव कर नया टेंडर जारी किया गया और अब पाइपलाइन शिफ्टिंग के साथ काम दोबारा शुरू हो सका है।

### 20 साल पुरानी मांग, आंदोलन और वार्दा का लंबा इतिहास

स्थानीय शिवसेना नेता एवं नवी मुंबई उप जिला प्रमुख सुरेश कुलकर्णी ने करीब 20 वर्ष पहले मनाया सदन में इस स्थान पर ब्रिज निर्माण की मांग उठाई थी। उस समय दो करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित स्काईवॉक योजना को रद्द कर दिया गया था। कुलकर्णी ने अफसोस जताते हुए कहा कि यदि उस समय यह काम हो गया होता, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके बाद फ्लाइंग ओवर की मांग को लेकर सड़क जाम, अधिकारियों का धेराव जैसे आंदोलन भी किए गए। वर्क ऑर्डर जारी हुआ, लेकिन ऐसा डिजाइन बनाया गया जिसमें पुल के नीचे से केवल रिक्शा और कारें ही गुजर सकती थीं। तकनीकी खामियों के कारण काम फिर अटक गया।

### ट्रैफिक से वाहन चालक परेशान

तुर्भे एमआईडीसी क्षेत्र में आने-जाने के लिए नागरिकों को व्यस्त ठाणे-बेलापुर रोड पार करनी पड़ती है। सड़क पार करते समय अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्थानीय नागरिकों के लिए यह सड़क पार करना हमेशा जान जोखिम में डालने जैसा रहा है।

### अधिकारियों की लापरवाही बनी देरी की वजह

सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जाधव ने कहा कि स्थानीय नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी की लगातार मांगों के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वर्षों तक लटका रहा। यदि यह ब्रिज 8-10 साल पहले बन गया होता, तो दर्जनों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल पाइपलाइन हटाने का कार्य जारी है। इसके पूरा होने ही तुर्भे स्टोर ब्रिज का निर्माण शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय से इंतजार की जा रही राहत मिलने की उम्मीद है।

# 110 परिवारों का सपना हुआ साकार

विधायक संजय केलकर ने सौंपी नए घरों की चाबियां

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र के बालकुंभ में बरसों से अपने हक के घर का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए गणतंत्र दिवस खुशियों की सांगत लेकर आया। स्थानीय विधायक संजय केलकर के प्रयासों से, पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) के बाद तैयार हुए आधुनिक घरों की चाबियां 110 परिवारों को सौंपी गईं। इससे पहले यहां की 35 इमारतों में रहने वाले परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किए जा चुके हैं। बालकुंभ क्षेत्र की 35 इमारतें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थीं, जिन्हें ठाणे मनपा ने खतरनाक घोषित कर नोटिस जारी किया था। घर खोने के डर से परेशान निवासियों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलेश पाटिल के नेतृत्व में विधायक संजय केलकर से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई थी। विधायक केलकर ने तुरंत मनपा और संबंधित विभागों के साथ फॉलो-अप शुरू किया। उनकी कोशिशों का नतीजा यह रहा कि न केवल सात पन्नों का विस्तृत लैंड सर्वे तैयार हुआ, बल्कि प्रत्येक परिवार को उनके नाम का प्रॉपर्टी कार्ड भी मिला।



### वल्स्टर योजना की बाधा को किया दूर

इन इमारतों के पुनर्विकास में सबसे बड़ी बाधा 'वल्स्टर डेवलपमेंट स्कീम' थी। इन इमारतों के वल्स्टर योजना में शामिल होने के कारण पुनर्विकास प्रक्रिया में देरी हो रही थी। विधायक केलकर ने प्रशासन के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा की और जोर दिया कि इन सरकारी/सोसायटी इमारतों को वल्स्टर स्कीम से बाहर रखा जाए ताकि काम तेजी से हो सके। अंततः प्रशासन ने उनकी मांग मानी और 'यशवंती नगर' को वल्स्टर स्कीम से बाहर कर दिया गया।

### 18 महीने में बनकर तैयार हुए आधुनिक आशियाने

रुकावटें दूर होने के बाद, अशोक वाटिका (दो विंग) और भारत कुटीर इमारतों का पुनर्विकास कार्य शुरू हुआ। महज 18 महीनों के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक केलकर ने 110 परिवारों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपीं। ये नए घर न केवल मजबूत हैं, बल्कि इनमें जीमिंग ट्रैक, गार्डन, जिम, पार्किंग और क्लब हाउस जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं।

### अगले चरण में 124 और परिवारों को मिलेंगे घर

इस अवसर पर नीलेश पाटिल और संजय पाटिल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधायक केलकर ने घोषणा की कि पुनर्विकास का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। जल्द ही 'लव कुटीर' और 'शत्रुघ्न कुटीर' इमारतों का काम भी शुरू किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में 124 और परिवारों को तय समय सीमा के भीतर उनके उच्च गुणवत्ता वाले घर मिल सकेंगे।

# उल्हासनगर महापौर चुनाव की तारीख तय

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

पीठासीन अधिकारी नियुक्त हुए रत्नागिरी जिला कलेक्टर मनुज जिंदल

उल्हासनगर महानगर पालिका के नव निर्वाचित सदस्यों में से महापौर और उप महापौर के चयन को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए 3 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। कोंकण मंडल के संभागीय आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए रत्नागिरी जिला कलेक्टर मनुज जिंदल को विशेष बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। नगर विकास विभाग द्वारा महापौर पद के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद उल्हासनगर मनपा आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर संभागीय आयुक्त को प्रस्ताव भेजा था। मुंबई



महानगरपालिका अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कोंकण संभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने महापौर और उप महापौर चयन की विशेष बैठक आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। इस बैठक में नव निर्वाचित नगरसेवकों में से पारदर्शी तरीके से शहर के प्रथम नागरिक और उप महापौर का चयन किया जाएगा।

**कलेक्टर को विशेष अधिकार, शहर की निगाहें 3 फरवरी पर**  
पीठासीन अधिकारी के रूप में कलेक्टर मनुज जिंदल को चुनाव प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें संपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालिया चुनाव परिणामों के बाद उल्हासनगर का राजनीतिक माहौल गर्मावा हुआ है और अब पूरे शहर की नजरें 3 फरवरी को होने वाली इस विशेष बैठक पर टिकी हुई हैं। आदेश की प्रतिलिपि मनपा आयुक्त सहित संबंधित प्रशासनिक विभागों को भेज दी गई है।

# मुख्यमंत्री ने किसानों के लॉन्ग मार्च की मांगों को लागू करने की दी गारंटी

दीपक पवार | मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत किए गए सभी दावों की पुनः जांच पर सहमति दी है। यह प्रक्रिया अगले तीन महीनों में पूरी की जाएगी। इसके तहत जंगल की जमीन पर कब्जा करने वाले योग्य दावेदारों को न्याय दिलाया जाएगा। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मंत्रियों को एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया है।



### किसानों की प्रमुख मांगें और बातचीत

लंबे मार्च के दौरान आदिवासी किसानों ने वन अधिकार कानून लागू करने, समुद्र में बहने वाले पानी का उपयोग स्थानीय लोगों और सूखे क्षेत्रों के लिए करने, पेसा भर्ती शुरू करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने जैसी मांगें रखीं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उडके, स्कूली शिक्षा मंत्री दादासाहेब भुरसे, वन मंत्री गणेश नाइक, मुख्य सचिव और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ दो घंटे तक इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

### मुख्यमंत्री की गारंटी और संतोषजनक समाधान

बैठक के बाद भी किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बातचीत फिर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगी गई मांगें लागू की जाएगी और इसमें किसी भी तरह की चूक नहीं होगी।

### मंत्रियों के स्तर पर निगरानी सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि मिनिस्टर लेवल पर लगातार निगरानी बनी रहेगी, ताकि लागू करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की कमी न हो। यह कदम किसानों और आदिवासी समुदाय के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राहत साबित होगा।

# वसई-विरार मनपा में अशोक शेळके बने भाजपा गुट नेता



डीबीडी संवाददाता | वसई

वसई-विरार शहर महानगरपालिका (वीवीसीएमसी) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गुट नेता के रूप में अशोक शेळके को सर्वसम्मति से चुना गया है। भाजपा के 43 नवनिर्वाचित नगरसेवकों की बैठक में उनके नाम पर आधिकारिक मुहर लगाई गई। वीवीसीएमसी चुनाव में भाजपा ने 43 सीटें जीतकर पहली बार सदन में एक शक्तिशाली विपक्षी दल के रूप में

अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नवनिर्वाचित गुट नेता अशोक शेळके पहले भाजपा युवा मोर्चा के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं और कई आक्रामक आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके हैं। वे स्थानीय नागरिक समस्याओं को मुखरता से उठाने और उनके समाधान के लिए पहचाने जाते हैं। प्रभाग क्रमांक 22 से उनका पूरा पैनाल विजयी रहा, जिससे उनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक क्षमता का पता चलता है।

### बैठक में प्रमुख नेताओं की मौजूदगी

नालासोपारा में आयोजित बैठक में भाजपा सांसद हेमंत सवरा, संगठन मंत्री हेमंत म्हात्रे, विधायक राजन नाईक, विधायक रमेशा दुबे-पंडित, जिलाध्यक्ष प्रभा पाटिल, पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल, महामंत्री मनोज बारोट, जोगेंद्र प्रसाद चौबे और विजेंद्र कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मनोज बारोट ने मौंडिया को जानकारी दी कि बैठक में गुट नेता का चयन सर्वसम्मति से किया गया और इसी निर्णय के आधार पर अशोक शेळके की नियुक्ति की गई।

# पारिवारिक कलह सुलझाना पड़ा भारी

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

भिवंडी के शांतिनगर थाना क्षेत्र में एक मामूली पारिवारिक विवाद में खौफनाक रूप ले लिया। न्यू आजाद नगर इलाके में 26 जनवरी की रात को तीन सगे भाइयों ने मिलकर एक 23 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी और तनाव का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

### तीन सगे भाइयों ने चाकू से गोदकर की हत्या, सभी गिरफ्तार



### बहन के झगड़े में सुलह कराना बनी रंजिशा की वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह एक दिन पुराना विवाद था। मृतक दिलशाद के भाई और शिकायतकर्ता गुलजार मकबूल अहमद शाह (25) ने 25 जनवरी को अपनी मौसरी बहन (मावस बहन) और उसके पति के बीच चल रहे झगड़े में मध्यस्थता कर मामला शांत कराया था। हालांकि, यह सुलह पति क्लेश के लोगों को नागवार गुजरी। इसी बात की रंजिशा रखते हुए आरोपियों ने गुलजार के परिवार को सबक सिखाने की साजिश रची।

### बीच सड़क पर दिया वारदात को अंजाम

26 जनवरी की रात न्यू आजाद नगर स्थित निजामिया हॉटल के पास आरोपियों ने दिलशाद (23) को धेर लिया। मुख्य आरोपी आसिफ अब्दुलहकीम शाह ने दिलशाद पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। जब गुलजार अपने भाई को बचाने आया, तो दूसरे आरोपी मुजफ्फर शाह ने उस पर लोहे की पाइप से हमला कर उसे भी घायल कर दिया।

# 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति बंद



डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत मुंबा, दिवा, कलवा, माजीवाडा-मानपाडा, वागले सहित कई प्रभाग समितियों को महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। MIDC की वॉटर सप्लाई स्क्रीम के तहत जांभूल वॉटर प्यूरिफिकेशन सेंटर रिजर्वॉयर (HRM) में 12 घंटे प्रेविटी चैनल क्रमांक 1, 2 और 3 पर चैनल अपग्रेडेशन तथा अजेंट मेंटेनेंस रिपेयर कार्य किया जाएगा। इस कारण गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को रात 12 बजे से

### इन क्षेत्रों में रहेगा पूरा असर

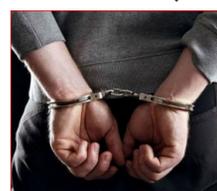
शटडाउन अवधि के दौरान ठाणे मनपा क्षेत्र के अंतर्गत दिवा, मुंबा प्रभाग समिति के 26 और 31 के कुछ हिस्सों को छोड़कर, कलवा प्रभाग समिति के अंतर्गत रूपादेवी पाडा, किसान नगर क्रमांक-2, नेहरू नगर तथा मानपाडा प्रभाग समिति के अंतर्गत कोलशेत खालवा गांव में 24 घंटे तक पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा, जलापूर्ति बहाल होने के बाद अगले 1 से 2 दिनों तक पानी कम दबाव से मिलने की संभावना है। महानगरपालिका के जल आपूर्ति विभाग ने नागरिकों से इस अवधि में पानी का संयमित उपयोग कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को रात 12 बजे तक कुल 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति बंद रहेगी।

# साढ़े 18 लाख रु की अवैध विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता | कल्याण

राज्य आबकारी विभाग (State Excise Department) के उड़न दस्ते ने कल्याण तहसील के ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने चोरी-छिपे चल रही विदेशी शराब की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 18.55 लाख रुपए से अधिक का माल जब्त किया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। ठाणे-2 के उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वाड) को गोपनीय सूचना मिली थी कि कल्याण के ग्रामीण इलाके में एक गोदाम से अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। इस सूचना के आधार पर 25 जनवरी को शाम करीब 7:35 बजे टीम ने छापेमारी की। मौके पर MH-05-FJ-9142 नंबर की एक चार पहिया गाड़ी पाई गई, जिसमें बिक्री के लिए अवैध रूप से विदेशी



### वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई

यह सफल ऑपरेशन राज्य आबकारी आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, संभागीय उपायुक्त प्रदीप पवार और उपायुक्त अनूप शिंदे के मार्गदर्शन में चलाया गया। जमीनी स्तर पर कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में इंस्पेक्टर दीपक परब, सब-इंस्पेक्टर टी.सी. चव्हाण, सब-इंस्पेक्टर आर.आर. सोनवणे और जवान एस.जी. राउत शामिल थे।

### 18.55 लाख का मुद्देमाल जब्त

टीम ने मौके पर पंचनामा कर गाड़ी, शराब का जखीरा और अन्य सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया। जब्त किए गए कुल सामान की कीमत 18,55,800 रुपए आकी गई है। आबकारी विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से दो आरोपियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ 'महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम, 1949' (Maharashtra Prohibition Act, 1949) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

# संजय गांधी नेशनल पार्क में अतिक्रमण हटाने पर बवाल

टीम पर पथराव के बाद पर्यटकों की एंट्री बंद

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई के फेफड़े कहे जाने वाले बोरीवली स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क (SGNP) में मंगलवार (27 जनवरी) को उस समय तनाव फैल गया, जब वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कराने गई टीम को स्थानीय निवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।



पर्यटकों के लिए पार्क के दरवाजे बंद

हिंसक झड़प और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए SGNP प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया। प्रशासन ने 27 जनवरी को पार्क का

मुख्य प्रवेश द्वार पर्यटकों और मॉर्निंग वॉर्कर्स के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर (साउथ) ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि

कानूनी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। फिलहाल पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है।

टीम पर अचानक हमला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

मंगलवार सुबह जैसे ही अतिक्रमण विरोधी दस्ता पार्क के भीतर पहुंचा, वहां मौजूद भीड़ ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई और असांजिक तत्वों ने वन विभाग और पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और इलाके की घेराबंदी कर दी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।

घर मिलने के बाद भी दोबारा कब्जा

1997 के हाईकोर्ट आदेश का क्रियान्वयन वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है, बल्कि यह 1997 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का हिस्सा है। कोर्ट ने नेशनल पार्क की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था। नियमों के अनुसार, 1995 की मतदाता सूची में शामिल परिवारों को ही पुनर्वास का लाभ दिया जाना था। इस योजना के तहत अब तक 11,000 से अधिक पात्र परिवारों को चांदिवली और पवई में शिफ्ट किया जा चुका है।

जांच में एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें से कई ऐसे हैं जो सरकारी योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक, लगभग 385 ऐसे परिवार हैं जिन्हें चांदिवली में पक्के घर मिल चुके थे, लेकिन उन्होंने उन घरों को छोड़कर या किराए पर देकर वापस नेशनल पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। कुछ लोग खुद को आदिवासी बताकर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

मुंबई में तय होगा चंद्रपुर का महापौर, लगातार बैठकों का दौर जारी



चंद्रपुर। चंद्रपुर महानगरपालिका के महापौर पद का चुनाव अब सीधे मुंबई की राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही स्थानीय स्तर पर सत्ता समीकरण साधने के लिए जोर-शोर से प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई में लगातार बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिसमें कांग्रेस नेता विजय वडेद्वीवार ने मातोश्री निवास पर शिवसेना (ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की, जबकि भाजपा के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और सुधीर मुनगंटीवार संख्याबल जुटाने के लिए समानांतर प्रयास कर रहे हैं। चंद्रपुर महानगरपालिका में कुल 66 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 34 मत जरूरी हैं। वर्तमान में भाजपा और शिवसेना मिलकर केवल 24 पांशेदों तक पहुंचते हैं, जबकि कांग्रेस के पास 27 हैं।

150 दिवसीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में कामगार विभाग रहा सबसे आगे

मंत्री ने अधिकारियों का किया सम्मान

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा आयोजित 150 दिवसीय ई-गवर्नेंस एवं सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम में कामगार विभाग ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम में शासकीय विभागों, संचालनालयों, आयुक्तलयों और क्षेत्रीय कार्यालयों का मूल्यांकन किया गया। 3,000 से कम मंजूरी पदसंख्या वाले विभागों की श्रेणी में कामगार विभाग ने 200 में से 185 अंक हासिल किए और प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। विभाग को विशेष प्रशंसनीय वर्ग में भी स्थान मिला है।

कार्यालयीन मूल्यांकन में अन्य उपलब्धियां



कार्यालयीन मूल्यांकन के अंतर्गत राज्य के 68 सर्वोत्तम आयुक्त एवं संचालक श्रेणी में कामगार विभाग के बॉयलर्स संचालनालय ने चौथा स्थान, जबकि कामगार आयुक्तलय ने पांचवां स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार विभाग ने न केवल अंक हासिल किए बल्कि अपने कार्यक्षमता और प्रशासनिक उत्कृष्टता का भी प्रमाण दिया।

कामगार मंत्री ने किया सम्मान

विभाग की इस उपलब्धि पर कामगार मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने मंत्रालय में उच्चपदस्थ अधिकारियों का सम्मान किया और उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। इस अवसर पर विभाग प्रमुख के रूप में मंत्री का भी सम्मान किया गया। समारोह में कामगार विभाग की प्रधान सचिव आई.ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच.पी. तुम्मीड, उपसचिव दीपक पोक्ले, उपसचिव स्वप्निल कापडणीस, उपसचिव रोशनी कदम, बॉयलर्स संचालनालय के संचालक गजानन वानखेडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

किशोरी पेडनेकर ने महायुति पर निशाना साधा

मुंबई। शिवसेना (ठाकरे) की समूह नेता और पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद अगर दोनों बटक दलों के बीच सहमति नहीं बनती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मंगलवार को पार्श्वेदों ने कोंकण भवन आयुक्त के पास समूह का पंजीकरण कराने के बाद नगर निगम मुख्यालय के सचिव अनुभाग में पार्श्वेद के रूप में पंजीकरण कराया, और इसी दौरान पेडनेकर ने अपनी बात रखी।

मालवणी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट



7 लोग झुलसे

मुंबई। मालवणी इलाके में मंगलवार सुबह गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। यह हादसा मालवणी गेट नंबर-8, एसी मरिजद के पास एक चॉल में हुआ, जहां गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में विस्फोट हो गया और चॉल में आग लग गई। घटना के तुरंत बाद बीएमसी फायर ब्रिगेड (MFB) को सुबह 9:25 बजे सूचना

मिली और मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, बिजली वितरण कंपनी के स्टाफ, एंबुलेंस और बीएमसी वाई स्टाफ पहुंच गए। आग मुख्य रूप से पहली मंजिल पर स्थित कमरे में सिलेंडर, गैस चूल्हे, एसी शीट, धरेलू सामान और गद्दों तक सीमित रही। फायर ब्रिगेड ने सुबह 9:42 बजे आग पर काबू पा लिया।

कुछ घायलों की हालत गंभीर

इस हादसे में कुल 7 लोग झुलसे हैं। इनमें से 4 घायलों को आधार अस्पताल और 3 को केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी का इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने चॉल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रारंभिक जांच में सिलेंडर से गैस रिसाव को मुख्य कारण माना जा रहा है।

क्या राऊत के लिए वंदनीय हो गई सोनिया गांधी : बन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राऊत पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के लिए बालासाहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और आनंद दिघे वंदनीय हैं, लेकिन संजय राऊत के लिए वास्तव में कौन वंदनीय है, यह सवाल जनता के सामने है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन सोनिया गांधी की कभी बालासाहेब ठाकरे ने कड़ी आलोचना की थी, वही आज उबाठा गुट और राऊत के लिए वंदनीय बन गई हैं।

उबाठा गुट पर कांग्रेस-एआईएमआईएम की गुलामी का आरोप



नवनाथ बन ने कहा कि राहुल गांधी और एआईएमआईएम अब राऊतों के लिए परमपूज्य हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और संजय राऊत ने कांग्रेस नेतृत्व की गुलामी के अलावा कुछ नहीं किया। बन ने कहा कि कौन किसका अंगवस्त्र है, इस पर निम्न स्तर की भाषा बोलने के बजाय जनता वास्तविक स्थिति अच्छी तरह जानती है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने उबाठा गुट को पहले ही घर बैठा दिया है और मुंबई में भाजपा-महायुति का ही महापौर बनेगा।

कोशयारी, आदिवासी मुद्दे और नेतृत्व पर सवाल

भगतसिंह कोशयारी को पद्म पुरस्कार मिलने पर राऊत की आलोचना को बन ने ओछी राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि कोशयारी ने राज्यपाल रहते हुए भ्रष्ट उबाठा सरकार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था। साथ ही, उन्होंने उबाठा गुट पर आदिवासी आंदोलन को भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अंत में बन ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 24 घंटे जनहित में काम कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे अब घर बैठे हैं और जनता उनसे सवाल पूछ रही है।

विधायक टूट और भाजपा में शामिल होने की अटकलें

उद्योग मंत्री उदय सामंत के भाजपा में जाने के राऊत के बयान पर पलटवार करते हुए नवनाथ बन ने कहा कि राऊत को ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के अहंकार से तंग आकर 40 विधायक अलग हुए। मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने जनता से मिलते थे, न कार्यकर्ताओं, विधायकों या मंत्रियों से, यही कारण था कि उनका साथ विधायकों ने छोड़ा।

50% बसें होंगी इलेक्ट्रिक

मंत्री प्रताप सरनाईक ने डिपो में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए आदेश

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC/SST महामंडल) ने सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से बदलने और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। परिवहन मंत्री और MSRTC के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने निगम को निर्देश दिया है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बस डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए बुनियादी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से स्थापित की जाएं।

50% बड़े को इलेक्ट्रिक करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य



निगम ने एक दीर्घकालिक और महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसके तहत भविष्य में MSRTC के बड़े की कुल बसें में से 50 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक होंगी। मंत्री सरनाईक ने स्पष्ट किया है कि केवल बसें खरीदना काफी नहीं है, बल्कि उनका सफल संचालन मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इसलिए, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा डिपो को इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में देरी न करें।

पेट्रोल-डीजल स्टेशनों की जगह EV को प्राथमिकता

मंत्री ने नीतिगत बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि भविष्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत जो भी ईंधन और ऊर्जा बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, उसमें पारंपरिक पेट्रोल और डीजल स्टेशनों के बजाय इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप



मुंबई। महाराष्ट्र में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर विपक्षी उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाने और सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की। सपकाल के अनुसार, सांगली जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पाटिल ने खुलेआम कहा कि विपक्ष के जीतने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वे अपना समय और धन बर्बाद न करें, जो आचार संहिता और निष्पक्ष चुनाव की भावना का उल्लंघन है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे को पत्र लिखकर मंत्री के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज करने और उनकी जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, "जब सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री विपक्षी उम्मीदवारों को डराने या उन्हें चुनाव से हटाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, तो यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है।"

मध्य रेल खुली निविदा सूचना

मध्य विद्युत अभियंता/निगम मध्य रेलवे, लोसरो मंजिल, नया प्रशासनिक भवन, दादामार्ग नवरोजी रोड, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई-400 001 भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए, नीचे दिए गए काम के लिए जाने-माने टेकेंदारों से बेवसाइट के जरिए ऑनलाइन खुली निविदा मांगता है- ई-निविदा सूचना संख्या: एलसी-इलेक्ट्रिक एच-जीसी-2025-26 दिनांक: 23.01.2026. कार्य का नाम: विद्युत निर्माण मध्य रेलवे मुख्यालय के लिए सामान्य सलाहकार की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव निवेदन (आरएफपी). लगभग निविदा लागत: ₹. 3,12,61,965.68 (रुपये तीन करोड़, बाइस लाख, इकसठ हजार, नौ सौ सैंड और अड़सठ पैसे केवल). बयाना संधि जमा (ईएमडी): ₹. 3,08,300/- (रुपये तीन लाख, छह हजार, तीन सौ केवल). बोली का प्रकार: सामान्य निविदा. बोली प्रणाली: दो पैकेट प्रणाली. बोली लगाने की शैली: प्रत्येक अनुसूची के लिए एक ही दर. निविदा दस्तावेज की कीमत: शून्य. पूर्ण होने की अवधि: मानसून सहित 24 (बीबीएस) महीने. प्रस्ताव की वैधता: 120 (एक सौ बीस) दिन. बेवसाइट का पता: <http://www.ireps.gov.in>; निविदा दस्तावेज की उपलब्धता: निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज ऊपर दी गई वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। पूर्व बोली समेत की तिथि और समय: 06.02.2026 को दोपहर 12:00 बजे; प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 09.02.2026; बोली शुरू होने की तिथि: 24.02.2026; बोली की निवृत्ति तिथि और समय: 10.03.2026 को दोपहर 3 बजे; बोली खोलने की तिथि और समय: 10.03.2026 को दोपहर 3 बजे; अगर उस तिथि को छुट्टी होती है तो बोली/निविदाएं अगले दिन ऊपर बताए गए समय पर खोले जाएंगी। संध/संयुक्त संध: अनुसूक्त-3 सदस्य; ऊपर बताए गए कामों के लिए निविदा देने वालों के लिए जरूरी टिप्पणी: क) निविदा प्रक्रिया केवल ई-निविदा के माध्यम से ही होगी। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को पहले आईआईटीएस वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। ख) इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपना प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने से पहले निविदा के नियमों और शर्तों, पात्रता मानदंडों आदि से संबंधित विवरण अवश्य देखें। ग) निविदा दस्तावेज और समय-समय पर जारी किए गए सुधित्व निविदा खुलने से कम से कम 15 दिन पहले इस वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं और इन्हें वेबसाइट पर देखा जा सकता है। घ) वित्तीय दर पृष्ठ में दर्ज और विधिवत डिजिटल हस्ताक्षरित दरें ही मान्य होंगी। ङ) संलग्न दस्तावेजों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर होने चाहिए। DE-850 अनुसूचित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना वंदनीय अपराध है।

पश्चिम रेलवे ने विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए

ट्रेन नंबर	प्रारंभ स्टेशन और गंतव्य स्टेशन	चलने के दिन	कब तक बढ़ाया गया
04828	बान्द्रा टर्मिनस - भगत की कोठी	रविवार	01.03.2026
04827	भगत की कोठी - बान्द्रा टर्मिनस	शनिवार	28.02.2026
09622	बान्द्रा टर्मिनस - अजमेर	सोमवार	23.02.2026
09621	अजमेर - बान्द्रा टर्मिनस	रविवार	22.02.2026
04728	वलसाड - हिसार	गुरुवार	26.02.2026
04727	हिसार - वलसाड	बुधवार	25.02.2026

समय-सारिणी, ठहराव (हॉल्ट) एवं रोक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर जाएं।

पश्चिम रेलवे  
wr.indianrailways.gov.in  
Like us on Facebook.com/WesternRly  
Follow us on X.com/WesternRly  
Instagram.com/WesternRly  
Follow us on YouTube.com/WesternRly  
https://www.youtube.com/WesternRly  
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता विभाग  
क्र. कार्य.अभि. (परि.) ज.मा.का./8133/दिनांक : 27/01/2026  
ई-निविदा सूचना  
बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा नीचे उल्लिखित विषयक कार्यों के लिए इच्छुक निविदाकारों से ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा विवरण एवं बिक्री की तिथि और समय तथा निविदा बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय से संबंधित विस्तृत जानकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका की वेबसाइट <http://portal.mcgm.gov.in> तथा महाटेंडर पोर्टल <http://mahatenders.gov.in> पर "निविदा अवलोकन" के अंतर्गत प्रकाशित / अपलोड की गई है।

क्रमांक	निविदा विवरण	निविदा का विषय
1	2026_MCGM_1271580_1 निविदा जारी एवं बिक्री की तिथि : 28.01.2026	"सहायक अभियंता जलकार्य (परि.) पश्चिम उपनगर / उत्तर-2 के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर, साईबाबा नगर, कैलासनगर तथा सोनू भोईर चाळ पॉपिंग स्टेशन स्थित पॉपिंग सेटों के संचालन, रखरखाव एवं संरक्षण का कार्य।"

निविदाकारों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी हेतु महाटेंडर पोर्टल <http://mahatenders.gov.in> तथा बृहन्मुंबई महानगरपालिका की वेबसाइट <http://portal.mcgm.gov.in> पर अवश्य देखें।

हस्ता/-  
कार्यकारी अभियंता (परि.)  
जल अभियंता विभाग  
पीआरओ/2780 / विज्ञा./ 2025-26

समय पर उपचार, बचाएँ प्राण।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

ठोस कचरा प्रबंधन विभाग (योजना)  
पत्र क्रमांक : उप मुख्य अभियंता / 6420 / SWM / योजना दिनांक : 27.01.2026  
ई-निविदा सूचना

विषय	:	"H/वेस्ट वार्ड में संकरी गलियों से कचरा संग्रहण हेतु छोटे कचरा ई-चाहन (ई-आंदो रिक्शा) की सेवेरै किराये पर लेना - 02 नग"
विभाग	:	ठोस कचरा प्रबंधन / उप मुख्य अभियंता (SWM) योजना
निविदा आईडी क्रमांक	:	2025_MCGM_1272056_1
बोली प्रारंभ दिनांक एवं समय	:	28.01.2026, प्रातः 11:00 बजे से
बोली समाप्ति दिनांक एवं समय	:	04.02.2026, सायं 16:00 बजे तक
वेबसाइट	:	<a href="https://mahatenders.gov.in">https://mahatenders.gov.in</a>
संपर्क अधिकारी विवरण	:	
(a) नाम	:	श्री हेमंत भुसारे, सहायक अभियंता (SWM) योजना
(b) दूरध्वनी	:	022-23844450
(c) मोबाइल नंबर	:	9762006449
(d) ई-मेल आईडी	:	ee1swm.pl@mcgm.gov.in

हस्ता/-  
पीआरओ / 2785/ विज्ञा./ 2025-26  
कार्यकारी अभियंता (ठोस कचरा प्रबंधन) - योजना  
समय पर उपचार, बचाएँ प्राण।

## संपादकीय

## कंक्रीट के जंगल और सूखती संवेदनाएं

मुंबई की लाइफलाइन कहीं जाने वाली लोकल ट्रेन में एक प्रोफेसर की मामूली बात पर हल्का केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के मानसिक स्वास्थ्य और गिरते नैतिक स्तर का एक भयावह आईना है। जब विकास की परिभाषा केवल चौड़ी सड़कों, चमकचमकी इमारतों और हाई-टेक अस्पतालों तक सिमट जाती है, तब समाज अक्सर अपनी आत्मा और सहनशीलता (Tolerance) खो देता है। मलाड स्टेशन पर हुई यह हृदयविदारक घटना इस बात का प्रमाण है कि हम 'सम्यता' की सीढ़ियाँ तो चढ़ रहे हैं, लेकिन 'संस्कार' की ढलान पर तेजी से फिसल रहे हैं। अक्सर किसी राष्ट्र की प्रगति का पैमाना उसकी जीडीपी, बुनियादी ढांचे और तकनीकी कौशल से मापा जाता है। नि:संदेह ये आवश्यक हैं, लेकिन क्या केवल ईंट-पत्थरों से बना ढांचा एक 'सक्षम राष्ट्र' कहलाने का हकदार है? राष्ट्र केवल मानचित्र पर खिंची लकीरों या कंक्रीट के ब्लॉक नहीं होते, राष्ट्र अपने नागरिकों के चरित्र, उनके आपसी व्यवहार और उनके 'बेहतर दिमाग' से बनते हैं। यदि एक नागरिक दूसरे नागरिक की जान लेने पर महज एक धक्के या रास्ते के विवाद में उतारू है, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारा सामाजिक ढांचा भीतर से खोखला हो चुका है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, आर्थिक दबाव और डिजिटल दुनिया के एकाकीपन ने मनुष्य को एक ऐसे 'प्रेरक कुंज' में बदल दिया है, जो कभी भी फट सकता है। 'तत्काल संतुष्टि' (Instant Gratification) के इस दौर में धैर्य या सहनशीलता जैसे शब्द शब्दकोशों तक सीमित रह गए हैं। सड़क पर मामूली कट लग जाने पर होने वाला 'रोड रेंज' हो या ट्रेन में सीट को लेकर होने वाला हिंसक झगड़ा—यह सब इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के भीतर का 'क्रोध प्रबंधन' पूरी तरह विफल हो चुका है। हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ संवाद की जगह हिंसा ने और तर्क की जगह आवेश ने ले ली है। एक बेहतर दिमाग ही एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल डिग्रियाँ बांटना या कुशल श्रमिक तैयार करना नहीं, बल्कि संवेदनशील नागरिक तैयार करना होना चाहिए। विडंबना देखिए कि जिस प्रोफेसर की हत्या हुई, वह स्वयं शिक्षा जगत के स्तंभ थे। यह घटना चीख-चीख कर कह रही है कि हमारे शिक्षा तंत्र और सामाजिक परिवेश में 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' (Emotional Intelligence) के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य को आज भी हमारे समाज में गंभीरता से नहीं लिया जाता। जब तक हम यह नहीं समझे कि कुंडा, निरंतर तनाव और अनियंत्रित क्रोध एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर उपचार आवश्यक है, तब तक ऐसी हिंसक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना कठिन होगा। राष्ट्र के स्वास्थ्य का अर्थ केवल अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिकों के मानसिक आरोग्य के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना भी है। यह समय केवल शोक मनाने का नहीं, बल्कि आत्म-मंथन का है। प्रशासन को कानून का खोफ पैदा करना ही होगा, लेकिन समाज के तौर पर हमें यह सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा भविष्य सौंप रहे हैं। क्या हम उन्हें केवल प्रतिस्पर्धी मशीनें बना रहे हैं या उन्हें एक-दूसरे का सम्मान करने वाला इंसान भी बना रहे हैं? सड़कें बन जाएंगी, आधुनिक अस्पताल खड़े हो जाएंगे और इमारतों की आसमान छू लेंगी, लेकिन यदि उनमें रहने वाला मनुष्य भीतर से हिंसक और संवेदनहीन रहा, तो यह भौतिक विकास बेमानी है। एक महान राष्ट्र की पहचान उसकी इमारतों की ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के विवेक और चरित्र की गहराई से होती है। अब समय आ गया है कि हम ईंट-गारे के निर्माण से आगे बढ़कर 'बेहतर दिमाग' और 'बेहतर इंसान' बनाने की नींव रखें।

शख्सियत लाला लाजपत राय

## राष्ट्रचेतना के प्रखर प्रहरी



लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ीके गांव (अब पाकिस्तान में स्थित) में हुआ था। वे ऐसे युग में जन्मे जब भारत पर ब्रिटिश शासन का दमनकारी साया था और समाज राजनीतिक चेतना से वंचित था। बाल्यकाल से ही उनके भीतर अन्याय के प्रति अस्वीकार और राष्ट्रप्रेम की भावना विद्यमान थी, जिसने आगे चलकर उन्हें भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया।

उनका पारिवारिक माहौल संस्कार, शिक्षा और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण था। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण आजाद विचारों वाले शिक्षक थे, जिनके व्यक्तित्व ने राष्ट्रप्रेम और सामाजिक चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। माता गुलाब देवी धार्मिक, सहनशील और त्यागमयी महिला थीं। माता-पिता के संस्कारों ने लाला लाजपत राय के व्यक्तित्व को वैचारिक मजबूती, आत्मनिश्चय और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से युक्त बना दिया। घर का वातावरण देश, धर्म, समाज और सेवा भाव से ओत-प्रोत था, जिसने उनके चरित्र को प्रारंभ से ही दृढ़ बना दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। आगे चलकर उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययन किया और कानून की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के दौरान ही वे सामाजिक सुधार आंदोलनों और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ गए थे। वे केवल डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि विचारशील, प्रश्न करने वाले और समाज के लिए सोचने वाले युवा के रूप में विकसित हो रहे थे। शिक्षा ने उनके भीतर विवेक, तर्क और वैचारिक स्पष्टता को जन्म दिया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत को करियर के रूप में अपनाया, लेकिन उनका जीवन केवल एक सफल वकील बनकर सीमित नहीं रहा। वे शीघ्र ही सामाजिक कार्य, शिक्षा, पत्रकारिता और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। उनका जीवन व्यक्तिगत उन्नति के बजाय राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित हो गया। उन्होंने समझ

लिया था कि भारत की वास्तविक मुक्ति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, शिक्षा और आत्मगौरव से संभव है। लाला लाजपत राय का योगदान बहुआयामी था। वे आर्य समाज से जुड़े और समाज सुधार आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना के निर्माण हेतु अनेक संस्थानों की स्थापना की, जिनमें दयानंद एंग्लो वैदिक (DAV) संस्थान प्रमुख हैं। वे 'लाल-बाल-पाल' त्रयी के प्रमुख स्तंभ थे—लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल—जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उग्र राष्ट्रवाद की वैचारिक दिशा दी। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों का निर्भीक विरोध किया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। उन्होंने कहा था—'मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील बनेगी।' यह कथन केवल शब्द नहीं, बल्कि राष्ट्रबलिदान की चेतना का उद्घोष था। लाला लाजपत राय का महत्व केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और राष्ट्रनिर्माता के रूप में है। वे आत्मसम्मान, स्वदेशी, शिक्षा और राष्ट्रचेतना के प्रतीक थे। उन्होंने भारत को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मबोध और आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया है।

## प्रिंटिंग मशीनें: आधुनिक क्षमता, भारत में उत्पादन और व्यापार



मुनीब चौरसिया युवा पत्रकार

प्रिंटिंग मशीनों ने आज सूचना, विज्ञान, पैकेजिंग और व्यवसायिक सामग्री के उत्पादन में केंद्रीय भूमिका निभाई है। तकनीकी प्रगति, डिजिटल समाधानों का विकास और बाजार की बदलती मांगों ने प्रिंटिंग उद्योग को तेज, सक्षम और प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है। आधुनिक प्रिंटिंग मशीनें अब केवल पृष्ठों पर स्याही लगाने का उपकरण नहीं रही, बल्कि वे दक्षता, गुणवत्ता, गति और लागत-प्रभावशीलता का संगम बन चुकी हैं। डिजिटल प्रिंटिंग प्रणाली बाजार की सबसे तेजी से बढ़ती तकनीकों में से एक बनी हुई है, जिसका भारत में राजस्व 2023 में लगभग 1457.4 मिलियन यूएसडी था और 2030 में लगभग 2674.0 मिलियन यूएसडी तक पहुंचने का अनुमान है।

यह 9.1 प्रतिशत की कम्पाउंड वार्षिक वृद्धि दर का संकेत देता है, जो निरंतर मांग की ओर इंगित करता है। डिजिटल मशीनें प्रति घंटे हजारों पृष्ठों का उत्पादन कर सकती हैं, जिससे छोटे बैच और ऑन-डिमांड प्रिंटिंग को प्रभावी तरीके से संभालना आसान हो गया है। उच्च-गति डिजिटल इंकजेट प्रिंटर बड़े पैमाने पर पैकेजिंग, विज्ञान और बड़े-फॉर्मेट प्रिंटिंग का कार्य समय और लागत बचाते हुए संपन्न करती हैं। फ्लेक्सोग्राफिक और ग्रेज्योर मशीनें पैकेजिंग और लेबलिंग उद्योग की रीढ़ बन गई हैं, जो रोल-टू-रोल उत्पादन में दक्षता बढ़ा रही हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर रही हैं। नई तकनीक वाली मशीनें उच्च गुणवत्ता और तेज उत्पादन क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे व्यवसायिक कंपनियों को समय पर उत्पादन पूरा करने में मदद मिलती है। भारत की प्रिंटिंग मशीनें उद्योग की स्थिति भी मजबूत हैं। देश के कुल प्रिंटिंग उद्योग का वार्षिक राजस्व 250,00 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है, जिसमें लगभग 250,000 प्रिंटिंग कंपनियाँ कार्यरत हैं और उद्योग लगभग 90,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। यह आंकड़े इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि भारत में प्रिंटिंग उद्योग पारंपरिक प्रिंटर से आगे बढ़कर एक बड़े आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, जो रोजगार, बाजार विस्तार और तकनीकी अपनाने के अवसर देता है। भारत में प्रिंटिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। स्थानीय निर्माता डिजिटल और ऑफसेट मशीनें विकसित कर रहे हैं, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए फ्रेंचाइजी समाधान प्रदान करती हैं। प्रिंट शॉप, पुस्तक प्रकाशन इकाइयों और पैकेजिंग कंपनियों अब ऑन-डिमांड और कस्टम प्रिंटिंग की ओर बढ़ रही हैं। खासकर इंक-टैक और बड़े-फॉर्मेट प्रिंटरों की लोकप्रियता बढ़ रही है, जो कम पृष्ठ-प्रति-लागत और ऊर्जा-कुशल समाधान प्रदान करते हैं। जापानी कंपनी एपसन भारत में इस तकनीक के विस्तार को बढ़ावा दे रही है, जहाँ उसकी स्थानीय वार्षिक बिक्री करीब 2,500 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँच चुकी है। भारत उद्योग में उन्नत प्रिंटिंग मशीनों का आयात भी उतना ही

महत्वपूर्ण है। जापान, अमेरिका और यूरोप से मशीनें उच्च गति, उन्नत रंग प्रबंधन और स्वचालित संचालन सुविधाओं के साथ आती हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 69 नए प्रिंटिंग प्रेस आयात किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख नाम कॉम्प्री, हाइडेलबर्ग और आरएमजीटी शामिल हैं, जबकि साथ ही करीब 2,000 पूर्व-उपयोग किए गए प्रेस भी देश में आयात होते हैं। यह दिखाता है कि उच्च तकनीकी और पुराने उपकरण दोनों की मांग बाजार में मौजूद है, जिससे छोटे और बड़े दोनों वर्ग के व्यवसाय लाभ उठाते हैं। मशीनों का व्यापार केवल बिक्री तक सीमित नहीं है। यह सेवा, स्पेयर पार्ट्स, रख-रखाव और सलाहकार सेवाओं तक फैल चुका है। पुराने प्रेसों की मरम्मत और उन्नत व्यवसाय भी फल-फूल रहा है। डेटा-आधारित मॉन्टो ने व्यवसायियों को मशीनों की स्थिति और क्षमता के आधार पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान की है। हालाँकि, छोटे व्यवसायों के लिए चुनौतियाँ भी हैं। भारत में कर प्रणाली और टैक्स नियम छोटे प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी की समस्या में डालते हैं, जिससे संचालन प्रभावित हो सकता है। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि जी-एस-टी की असंगत दरें छोटे प्रिंटरों को वित्तीय दबाव में डाल चुकी हैं, जिससे उन्हें अपने खर्चों और कर्मचारियों के वेतन का प्रबंधन करना कठिन हो गया है। बाजार में अक्सर लगातार बढ़ रहे हैं। तकनीक और मशीनों की उन्नति नई कंपनियों के लिए अवसर खोल रही है। डिजिटल प्रिंटिंग और कस्टम प्रिंटिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर



जिससे छोटे और बड़े दोनों वर्ग के व्यवसाय लाभ उठाते हैं। मशीनों का व्यापार केवल बिक्री तक सीमित नहीं है। यह सेवा, स्पेयर पार्ट्स, रख-रखाव और सलाहकार सेवाओं तक फैल चुका है। पुराने प्रेसों की मरम्मत और उन्नत व्यवसाय भी फल-फूल रहा है। डेटा-आधारित मॉन्टो ने व्यवसायियों को मशीनों की स्थिति और क्षमता के आधार पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान की है। हालाँकि, छोटे व्यवसायों के लिए चुनौतियाँ भी हैं। भारत में कर प्रणाली और टैक्स नियम छोटे प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी की समस्या में डालते हैं, जिससे संचालन प्रभावित हो सकता है। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि जी-एस-टी की असंगत दरें छोटे प्रिंटरों को वित्तीय दबाव में डाल चुकी हैं, जिससे उन्हें अपने खर्चों और कर्मचारियों के वेतन का प्रबंधन करना कठिन हो गया है। बाजार में अक्सर लगातार बढ़ रहे हैं। तकनीक और मशीनों की उन्नति नई कंपनियों के लिए अवसर खोल रही है। डिजिटल प्रिंटिंग और कस्टम प्रिंटिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर

पैकेजिंग उद्योग में, जहाँ उच्च गुणवत्ता और तेज उत्पादन की आवश्यकता अधिक है। भारतीय व्यापार को एक बड़ा लाभ यह है कि पैकेजिंग प्रिंटिंग ने उद्योग को उद्वारण से बढ़कर नए विस्तार की ओर धकेला है, जिससे यह संकट के समय भी जीवित और विकसित रहा है। आने वाले वर्षों में डिजिटल प्रिंटिंग की मांग और भी बढ़ने की संभावना है। ऑन-डिमांड प्रिंटिंग, कस्टम प्रिंट और पैकेजिंग उद्योग की वृद्धि नए अवसर खोल रही है। उन्नत डिजिटल प्रणाली, इंटरनेट-सक्षम मशीनें और ऊर्जा-कुशल समाधान भविष्य में उद्योग का केंद्र बनेंगे। आज प्रिंटिंग मशीनें केवल उपकरण नहीं हैं, बल्कि व्यवसाय की रीढ़ बन चुकी हैं। आधुनिक मशीनों की क्षमता, विदेशी तकनीक और घरेलू उत्पादन ने भारत के प्रिंटिंग उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर दिया है। छोटे व्यवसायों से लेकर बड़े कॉर्पोरेट प्रिंट हाउस तक, ये मशीनें उत्पादन, गुणवत्ता और लागत के दृष्टिकोण से उद्योग को नई दिशा दे रही हैं। प्रिंटिंग उद्योग न केवल व्यवसायिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। डिजिटल और ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक ने व्यवसायों को तेज, भरोसेमंद और लागत-प्रभावी समाधान दिया है। भविष्य में तकनीक और नवाचार के साथ, भारत का प्रिंटिंग उद्योग और अधिक विकसित होने की संभावना रखता है। प्रिंटिंग मशीनें व्यवसाय, सूचना और कला के संगम का प्रतीक हैं। आधुनिक मशीनें उच्च गुणवत्ता, तेज उत्पादन और लागत-कुशल समाधान प्रदान करती हैं। भारतीय उद्योग इन अवसरों को पहचान कर तकनीक अपनाने में तेजी दिखा रहा है। आने वाले समय में प्रिंटिंग उद्योग का महत्व और बढ़ेगा, क्योंकि डिजिटल प्रिंटिंग और कस्टम प्रिंटिंग की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में प्रिंटिंग मशीनों का उद्योग अब न केवल उत्पादन के लिए, बल्कि नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है। यह उद्योग व्यवसाय, तकनीक और अर्थव्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित हो चुका है।

## जीवन मंत्र

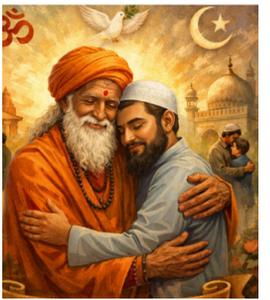
आज के समय में धर्म को अक्सर बाहरी पहचान, रीति-रिवाज और दिखावे तक सीमित कर दिया गया है। पूजा-पाठ, वेशभूषा और परंपराएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन वे तब तक अधूरी हैं, जब तक उनमें मानव के पति संवेदना न हो।

धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना है, न कि उसे एक-दूसरे से अलग करना। जब धर्म प्रेम, करुणा और संवेदना से जुड़ता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। मानव प्रेम ही वह आधार है, जिस पर किसी भी धर्म की इमारत खड़ी होती है। यदि धर्म में मानवता नहीं है, तो वह केवल कर्मकांड बनकर रह जाता है। सभी धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्रीय संदेश एक ही है—प्रेम। चाहे वह "वसुधैव कुटुंबकम्" का विचार हो, "सर्वे भवन्तु सुखिनः" का कामना हो, या फिर "अपने पड़ोसी से प्रेम

## मानव प्रेम ही असल में धर्म

करो" का उपदेश—हर जगह मानव प्रेम को ही धर्म का सार माना गया है। धर्म का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर करुणा, सहनशीलता और सहअस्तित्व की भावना जगाना है। आज के समय में धर्म को अक्सर बाहरी पहचान, रीति-रिवाज और दिखावे तक सीमित कर दिया गया है। पूजा-पाठ, वेशभूषा और परंपराएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन वे तब तक अधूरी हैं, जब तक उनमें मानव के प्रति संवेदना न हो। भूखे को भोजन देना, दुखी को दांडस बंधाना, पीड़ित के साथ खड़ा होना—यही धर्म का वास्तविक आचरण है। मानव प्रेम

व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, तभी हमारे भीतर सच्चा धर्म जन्म लेता है। प्रेम हमें सिखाता है कि हर मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या विचारधारा का हो, सम्मान और करुणा का अधिकारी है। धर्म यदि विभाजन पैदा करे, नफरत सिखाए या हिंसा को जन्म दे, तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है। सच्चा धर्म वह है जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाए। इसलिए कहा जा सकता है कि मानव प्रेम ही असल में धर्म है—क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहीं ईश्वर है, और जहाँ करुणा है, वहीं सच्ची आस्था का वास है।



## जीवन ऊर्जा

जोसे जूलियन मार्टी का जन्म 28 जनवरी 1853 को हवाना (क्यूबा) में हुआ। वे क्यूबा के राष्ट्रीय नायक, क्रांतिकारी, लेखक और दार्शनिक थे। स्पेनिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका जीवन दर्शन मानव गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आत्मसम्मान पर आधारित था।

## स्व

तंत्रता का मूल्य त्याग से चुकाया जाता है। मनुष्य की पहली जिम्मेदारी उसकी गरिमा है। राष्ट्र केवल भूमि नहीं, विचार होता है। बिना नैतिकता के स्वतंत्रता खोखली है। शिक्षा ही सच्ची क्रांति का आधार है। अन्याय के सामने मौन भी अपराध है। मानवता किसी सीमा में बंधी नहीं होती। प्रेम और साहस से ही राष्ट्र बनते हैं। स्वतंत्र मन ही स्वतंत्र देश रचता है। गुलामी शरीर की नहीं, चेतना की होती है। विचारों की आजादी सबसे बड़ा हथियार है। जो अन्याय सहता है, वह उसे मजबूत करता है। सच्चा देशभक्त मानवता से शुरू करता है। संस्कृति आत्मा की आवाज है। भय से नहीं, विश्वास से समाज चलता है। शब्द भी तलवार जितने शक्तिशाली होते हैं। आत्मसम्मान के

जोसे जूलियन मार्टी : जन्म 28 जनवरी 1853

जन्म

## सच्ची स्वतंत्रता सेवा और करुणा से आती है

बिना जीवन अधूरा है। राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं में होता है। स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, संघर्ष का फल है। सत्य हमेशा सत्ता से बड़ा होता है। जो मानवता से प्रेम नहीं करता, वह देश से भी नहीं कर सकता। न्याय के बिना शांति असंभव है। विचारों की गुलामी सबसे खतरनाक है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना ही दर्शन है। क्रांति पहले मन में जन्म लेती है। नैतिक साहस सबसे बड़ी शक्ति है। स्वतंत्रता की रक्षा रोज करनी पड़ती है। शब्दों से विचार और विचारों से इतिहास बनता है। मानव गरिमा हर संघर्ष का केंद्र है। सच्ची स्वतंत्रता सेवा और करुणा से आती है। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह



सबके लिए हो। जो डर पर जीत पा लेता है, वही सच में आजाद होता है। राष्ट्र की आत्मा उसके नैतिक चरित्र से पहचानी जाती है। विचारों को कैद नहीं किया जा सकता, वे समय से आगे चलते हैं। जहाँ अन्याय होता है, वहाँ संघर्ष जन्म लेता है। बल से दबाया गया सत्य और अधिक प्रखर होकर लौटता है। सच्चा साहस हथियार उठाने में नहीं, सत्य बोलने में है। मानव प्रेम के बिना देशभक्ति केवल नारा बन जाती है। जो शिक्षा को कमजोर करता है, वह भविष्य को अंधकार देता है। स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रक्षा जागरूक नागरिक करता है।

## सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

## देवर्षि नारदः निरंतर गतिशील भक्ति और मानवता का संदेश

सनातन धर्म की परंपरा में देवर्षि नारद एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व हैं, जिनका जीवन उद्वारण नहीं, बल्कि निरंतर गति का प्रतीक है। वे कहीं रुकते नहीं, किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं बिताते। इसके पीछे केवल कोई श्राप नहीं, बल्कि सृष्टि, धर्म और लोककल्याण से जुड़ा गहरा दर्शन निहित है। नारद जी का जीवन यह सिखाता है कि जब उद्देश्य व्यापक हो, तब व्यक्ति की यात्रा भी व्यापक हो जाती है। देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी के सात मानस पुत्रों में से एक माना गया है। देवताओं के

ऋषि होने के कारण उन्हें 'देवर्षि' की उपाधि प्राप्त हुई। वे अपने ज्ञान, विवेक और सत्यप्रियता के कारण देवताओं और दैत्यों—दोनों के बीच समान सम्मान प्राप्त करते थे। नारद अजर-अमर हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। उनके जीवन का केंद्र भक्ति है, किंतु यह भक्ति संकीर्ण नहीं, बल्कि लोकमंगल की भावना से परिपूर्ण है। पुरुषों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा था। किंतु नारद जी का मन सांसारिक विस्तार की अपेक्षा आत्मिक उन्नति की ओर अधिक उन्मुख था। उन्होंने पिता के आदेश को स्वीकार नहीं किया। इस कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दिया। यह श्राप नारद जी के लिए बंधन नहीं, बल्कि उन्हें सांसारिक मोह से मुक्त करने का साधन बन गया, जिससे वे संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वतंत्र होकर विचारण कर सके। देवर्षि नारद को सृष्टि का प्रथम संदेशवाहक भी कहा जाता है। वे तीनों लोकों—देवलोक, मृत्युलोक और पाताललोक—में निरंतर भ्रमण करते हुए विचारों, सूचनाओं और चेतना का आदान-प्रदान करते थे। वे केवल समाचार नहीं पहुंचाते थे, बल्कि जहाँ भी जाते, वहाँ धर्म, विवेक और आत्मबोध की ज्योति प्रज्वलित करते थे। उनका उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना और ईश्वर से जोड़ना था। नारद जी के निरंतर भ्रमण के पीछे प्रजापति दक्ष से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा मिलती है। दक्ष प्रजापति की पत्नी आसक्ति से दस हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे। नारद जी ने उन पुत्रों को वैराग्य और मोक्ष का उपदेश दिया, जिससे वे सांसारिक राजपाठ छोड़कर आत्मिक मार्ग पर अग्रसर हो गए। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को यह श्राप दिया कि वे किसी भी एक स्थान पर दो घड़ी से अधिक नहीं रुक पाएंगे। दक्ष को भय था कि यदि नारद जी समस्त मानव समाज को वैराग्य का उपदेश देने लगे, तो सृष्टि का विस्तार रुक जाएगा। यह श्राप भी वास्तव में नारद जी को लोककल्याण की सतत यात्रा पर बनाए रखने का माध्यम बन गया। वे एक स्थान पर रुकते नहीं, क्योंकि उनका कार्य किसी एक व्यक्ति या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वे चेतना के यात्री हैं, जिनका धर्म स्थिरता नहीं, बल्कि प्रवाह है।

कठोर तपस्या और साधना के बल पर नारद जी ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। वे भक्ति और संकीर्तन के आद्य आचार्य माने जाते हैं। उनकी वीणा 'महती' से निरंतर 'नारायण-नारायण' की ध्वनि निकलती रहती है, जो यह संदेश देती है कि ईश्वर स्मरण ही जीवन का सार है। उनकी भक्ति कहीं नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से जुड़ी हुई है। देवर्षि नारद का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को संसार से काटना नहीं, बल्कि उसे अधिक मानवीय बनाना है। उनका वैराग्य पलायन नहीं, बल्कि मोह से मुक्ति है।



कठोर तपस्या और साधना के बल पर नारद जी ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। वे भक्ति और संकीर्तन के आद्य आचार्य माने जाते हैं। उनकी वीणा 'महती' से निरंतर 'नारायण-नारायण' की ध्वनि निकलती रहती है, जो यह संदेश देती है कि ईश्वर स्मरण ही जीवन का सार है। उनकी भक्ति कहीं नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से जुड़ी हुई है। देवर्षि नारद का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को संसार से काटना नहीं, बल्कि उसे अधिक मानवीय बनाना है। उनका वैराग्य पलायन नहीं, बल्कि मोह से मुक्ति है।



पंडित कैलाशचंद्र शर्मा वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक। मो. नं. 9425980556

## अपने विचार

किसी भी मुद्दे पर विरोध करने से पहले तथ्यों और प्रक्रिया को समझना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन संवाद और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखनी चाहिए।



-संजय निषाद अध्यक्ष, निषाद पार्टी

'योगी विरोधी खुश फहमी ना पालें, मेरा कथन योगी जी के विरुद्ध नहीं है, मैं उनके प्रति सम्मान, स्नेह एवं शुभकामना का भाव रखती हूँ किंतु मैं इस बात पर कायम हूँ कि प्रशासन कानून-व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण करे लेकिन किसी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है, यह सिर्फ शंकराचार्य या विद्वत परिषद कर सकते हैं।'



-उमा भारती वरिष्ठ नेत्री, भाजपा

'हमारी कुर्बानियों की बदौलत ही आज भाजपा सत्ता में है। हम इसे सहन नहीं करेंगे कि एक तरफ हमें महायुति धर्म का पालन करने को कहा जाए, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता ऐसे बयान दें। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा।'



-संजय शिरसाट नेता, शिवसेना (शिदे)

यूजीसी के नए नियमों का विषय बहुत गंभीर है इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ। जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच-समझकर बोलूंगा क्योंकि यह समाज से जुड़ा मुद्दा है। कोई सामंजस्य निकलना चाहिए इसलिए बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं -बृजभूषण शरण सिंह नेता, भाजपा



## अपने विचार

डीबीडी कार्यालय  
ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001  
indiagroundreport@gmail.com  
भेज सकते हैं।



## न्यूज ग्रीप

## सक्रिय हुआ मौसम, बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

देहरादून। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश में खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश और बर्फबारी का अर्रेंज अलर्ट घोषित किया गया है। सभी जिलों में सतकंता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खराब मौसम को देखते हुए देहरादून, अल्मोड़ा और बागेश्वर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक फरवरी तक राज्य में रुक-रुक कर वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना बनी रहेगी। स्थिति पर नजर रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं।

## यूजीसी के विरोध में सांसदों को भेजी

## गई चूड़ियां

रायबरेली। यूजीसी से जुड़े विवादाित प्रावधानों के खिलाफ रायबरेली में विरोध का अलग अंदाज देखने को मिला। किसान नेताओं और सामाजिक संगठनों ने सवर्ण वर्ग के सांसदों को प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां भेजकर नाराजगी जताई। भाजपा किसान मोर्चा नेता रमेश बहादुर सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं और इसी असंतोष के चलते यह संदेश दिया गया है। वहीं, हिंदू रक्षा दल से जुड़े नेताओं ने भी आरोप लगाया कि यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर निर्वाचित प्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। इस प्रतीकात्मक विरोध के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और सरकार से यूजीसी से संबंधित निर्णयों पर पुनर्विचार की मांग की गई।

## संविधान मूल्यों का संकल्प

अम्बेडकरनगर। जनपद अम्बेडकरनगर के बेवना जन शिक्षण केंद्र, कुटियावा मुख्यालय पर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर संस्था की सचिव पुष्पा पाल, संस्था सदस्य डॉ ओम अनादी गुप्ता, हरिराम, लालता प्रसाद, जन शिक्षण केंद्र के सामाजिक कार्यकर्ता, गांव के गणमान्य लोग, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद संस्था सचिव पुष्पा पाल ने संविधान के मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि संविधान ने महिलाओं को बराबरी, सम्मान और अधिकार की शक्ति दी है। साथ ही जन शिक्षण केंद्र द्वारा नारी संघ कार्यालय और जन शिक्षण फार्मर प्रोड्यूसर कार्यालय पर भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। सावित्रीबाई फुले नारी संघ ने विभिन्न पंचायतों में नारी संघ बहनों के साथ उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित करते हुए महिला सशक्तिकरण को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताया। कार्यक्रम का समापन बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ, मिष्ठान वितरण और देशभक्ति नारों के साथ किया गया।

## UGC के खिलाफ UP में सड़क पर युवा

सूबे के कई जिलों में छात्रों और संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन  
प्रस्तावित कानून को बताया असमानता और तनाव बढ़ाने वाला

एजेंसी | लखनऊ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्तावित नए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध की लहर तेज होती जा रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को छात्रों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उत्तरकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से कानून को वापस लेने की मांग उठाई। विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में छात्रों ने धरना देकर यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि नया कानून उच्च शिक्षा व्यवस्था में असमानता को बढ़ावा देगा और इससे उनकी पढ़ाई व भविष्य दोनों प्रभावित होंगे। धरने के कारण विश्वविद्यालय परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।



## कानपुर में प्रधानमंत्री को लिखी पती

कानपुर में विरोध का स्वर और भी अलग अंदाज में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जूही मंडल उपाध्यक्ष आकाश ठाकुर ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूजीसी के नए नियमों पर पुनर्विचार करने की अपील की। उनका कहना है कि यह कानून समाज और शिक्षण संस्थानों में विभाजन को और गहरा कर सकता है। वहीं, जिलों में सामाजिक संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर तखियों के साथ प्रदर्शन कर जोरदार नारे लगाए।

## भाजपा

## उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी

वाराणसी में भी यूजीसी बिल 2026 के खिलाफ विरोध मुखर रहा। अस्सी क्षेत्र निवासी और भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुधीर मिश्रा ने कहा कि इस बिल को लेकर असंतोष व्यापक है और केंद्र सरकार को समय रहते संशोधन करना चाहिए। वाराणसी जिला मुख्यालय पर भी कई संगठनों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। खास बात यह रही कि सतारूद दल से जुड़े बुध स्तर से लेकर महानगर स्तर तक के कई कार्यकर्ताओं ने भी खुले तौर पर संशोधन की मांग की।

## जौनपुर में सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन

जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर उस समय गूंज उठा, जब सवर्ण आर्मी के हजारों कार्यकर्ताओं ने यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र को सौंपा गया। संगठन के नेता प्रवीण तिवारी ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग यूजीसी बिल को पूरी तरह समाप्त करने की है।

## एससी-एसटी एक्ट है तो यूजीसी क्यों?

रायबरेली में भाजपा किसान मोर्चा नेता रमेश बहादुर सिंह और हिंदू रक्षा दल ने विरोध जताते हैं। दूसरी तरफ, बिजनौर में सवर्ण समाज, सवर्ण आर्मी और क्षत्रिय राजपूत सभा समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल शोभा शर्मा ने सवाल उठाया कि जब पहले से एससी-एसटी एक्ट लागू है, तो यूजीसी के नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। अलीगढ़ में राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए यूजीसी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्कर शर्मा ने कहा कि छात्रों को बांटने वाले इस कानून को किसी भी सुस्त में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी यूजीसी के नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध सभाएं आयोजित की गईं।

## बैंकों में पेन डाउन, ATM पर लगी कतार

बैंक हड़ताल से लेनदेन प्रभावित, लखनऊ सहित कई जिलों में प्रदर्शन  
UFBU के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल का यूपी में भी दिखा असर

एजेंसी | लखनऊ

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर मंगलवार को हुई देशव्यापी बैंक हड़ताल का व्यापक असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। प्रदेशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेन-देन सहित अधिकांश सेवाएं पूरी तरह ठप रही। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, हरदोई समेत कई जिलों में बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन और रैलियों के जरिए अपनी मांगों को मुखर किया। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में नकदी जमा-निकासी, ड्राफ्ट निर्माण, केवाईसी व पासबुक अपडेट जैसी सेवाएं बाधित रही। जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ा। कई स्थानों पर एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगीं रहीं, वहीं कुछ एटीएम में नकदी समाप्त होने की भी शिकायतें सामने आईं।

## बैंकिंग से इतर भी कार्यों का बोझ



एनओबीओ यूनियन (उत्तर प्रदेश) के उपाध्यक्ष और यूको बैंक के प्रबंधक राजीव रंजन केशरी ने बताया कि बैंक कर्मचारी केवल नियमित बैंकिंग कार्य ही नहीं करते, बल्कि जनधन योजना, मुद्रा ऋण योजना सहित केंद्र व राज्य सरकार की अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं को भी जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग और इंडियन बैंक एसोसिएशन की ओर से पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लेकर कई बार आवासन दिए गए, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई। राजधानी लखनऊ में यूएफबीयू जिला इकाई के आह्वान पर सुबह 10 बजे से बैंककर्मी हड़ताल पर चले गए। अधिकारियों और कर्मचारियों ने शाखाओं के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि बैंक कर्मियों की मांगें पूरी तरह जायज हैं, लेकिन सरकार लंबे समय से

## इन्हें नजरअंदाज कर रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

## प्रदेशभर में एकजुटता का प्रदर्शन

लखनऊ के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी बैंक कर्मियों ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कुल मिलाकर हड़ताल ने न केवल बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि आम ग्राहकों को भी दिनभर असुविधा का सामना करना पड़ा।

शंकराचार्य का समर्थन करने वाले अलंकार अग्निहोत्री के त्यागपत्र के बाद एक और इस्तीफा

डिटी कमिश्नर प्रशांत ने राज्यपाल को भेजा दो पेज का इस्तीफा

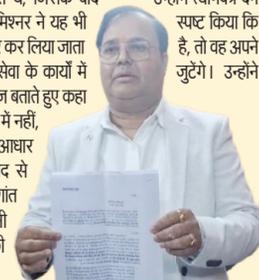
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद के बाद सूबे में बढ़ी सियासत

एजेंसी | अयोध्या

प्रयागराज माघ मेले से जुड़े शंकराचार्य विवाद को लेकर उपजे सियासी और प्रशासनिक घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा कदम सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अयोध्या में तैनात जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने दो पृष्ठों का इस्तीफा राज्यपाल को प्रेषित कर अपने निर्णय के कारण स्पष्ट किए हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा हाल ही में दिए गए इस्तीफे के बाद यह दूसरा मामला है, जब किसी वरिष्ठ अधिकारी ने शंकराचार्य से जुड़े विवाद को आधार बनाकर बकाए छोड़ने का फैसला किया हो। इससे पहले अलंकार अग्निहोत्री ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में त्यागपत्र देकर प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी थी।

अब योगी के समर्थन में GST अफसर ने छोड़ी नौकरी

## "मुख्यमंत्री का भीडिया से बातचीत में प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यह कदम उठाया है। उनका कहना था कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ की गई टिप्पणी उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहत करने वाली लगी। उन्होंने कहा, "मैं उत्तर प्रदेश का कर्मचारी हूँ, इसी प्रदेश से वेतन पाता हूँ। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री के अपमान को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।" प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि पिछले तीन दिनों से इस हड़ताल से मानसिक रूप से व्यथित थे, जिसके बाद उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी यदि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता निर्जी संसाधनों से समाज सेवा के कार्यों में इसे अपने अंतर्गत की आवाज बताते हुए कहा कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के आधार पर लिया गया है। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद प्रशांत कुमार सिंह ने फोन पर अपनी पत्नी को इस निर्णय की जानकारी दी।



## केंद्रीय बजट 2026-27 की उलटी गिनती शुरू, नॉर्थ ब्लॉक में बना हलवा

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्र सरकार के आगामी आम बजट की तैयारियां अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। इस क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित पारंपरिक 'हलवा समारोह' में सहभागिता कर बजट प्रक्रिया के अंतिम चरण की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने बजट निर्माण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं तथा बजट प्रेस का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

## पूरी तरह डिजिटल होगा केंद्रीय बजट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2026-27 का पूर्ण केंद्रीय बजट भी पूरी तरह डिजिटल होगा। इससे पहले के पांच पूर्ण बजट और एक अंतिम बजट की तरह इस बार भी बजट से जुड़े सभी

## नार्थ ब्लॉक में हुई बजट की छपाई

रायसीना हिल्स स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित इस समारोह में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के सभी प्रमुख विभागों के सचिव और बजट प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय का अधिकांश प्रशासनिक अमला सितंबर 2025 में कर्तव्य भवन स्थित नए केंद्रीय सचिवालय परिसर में स्थानांतरित हो चुका है, हालांकि बजट छपाई की परंपरा अब भी नॉर्थ ब्लॉक से ही निभाई जा रही है।



दस्तावेज—वाषिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांगों और वित्त विधेयक—केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप' के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। हलवा समारोह बजट निर्माण की गोपनीय प्रक्रिया से जुड़ी एक पुरानी परंपरा है। बजट की छपाई शुरू होने से पहले यह आयोजन उन अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में किया जाता है, जो बजट तैयार करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इस समारोह के बाद वित्त मंत्रालय से जुड़े लगभग 60 से 70 अधिकारी और कर्मचारी 'लोक-इन पीरियड' में प्रवेश करते हैं। इस दौरान वे बजट पेश होने तक न तो मंत्रालय परिसर से बाहर जा सकते हैं और न ही बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। इस गोपनीय व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बजट से संबंधित कोई भी संवेदनशील जानकारी समय से पहले सार्वजनिक न हो।

## भारत-EU के समझौते से बाजार ने पकड़ी रफ्तार दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद सुखद अंत, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी

एजेंसी | नई दिल्ली

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए व्यापार समझौते के उत्साह ने आज घरेलू शेयर बाजार को मजबूती दी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला, जबकि निफ्टी ने मामूली बढ़त के साथ ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआती बिकवाली के बाद खरीदारों की शुरुआती बिकवाली से दिनभर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अंतिम घंटे में व्यापक खरीदारी ने दोनों प्रमुख मजबूती प्रदान की।



## 17 हरे तो 13 शेर लाल निशान में हुए वलोज

आज सेंसेक्स के 30 में से 17 शेर हरे निशान में और 13 लाल निशान में बंद हुए, जबकि निफ्टी के 50 शेयरों में 31 शेर लाल में और 19 शेर लाल में बंद हुए। दिनभर के कारोबार में बाजार के बड़े शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेज, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज में तेजी देखी गई, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, एशियन पेट्रोल, एटर्नल और बजाज फिनसर्व में कमजोरी रही।

## 126.75 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी बंद

अंतिम आंकड़ों के अनुसार, सेंसेक्स 81,857.48 अंक पर 319.78 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,175.40 अंक पर 126.75 अंक की मजबूती के साथ कारोबार का समापन किया। इस मजबूती से निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.02 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ और बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 454.58 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

## 7406 शेयरों में दिनभर हुई ट्रेडिंग

आज बीएसई में कुल 4,473 और एनएसई में 2,933 शेयरों में सक्रिय ट्रेडिंग हुई। दिनभर के उतार-चढ़ाव और अंतिम घंटे की लिवाली ने बाजार में संतुलन बनाए रखा और निवेशकों के लिए लाभ का अवसर सुनिश्चित किया।

## कस्तूरी मेटल का आईपीओ लांच

तीन फरवरी को SME प्लेटफॉर्म पर हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली। स्टील फाइबर उत्पाद बनाने वाली कस्तूरी मेटल कर्पोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार को अपने आईपीओ का सर्वप्रारंभिक शुरु कर दिया। इस इश्यू की कुल राशि 17.61 करोड़ रुपये है, जिसमें निवेशक 29 जनवरी तक बोली लगा सकते हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट 30 जनवरी को होगा और 2 फरवरी को शेयर निवेशकों के डोमैट अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। अनुमान है कि 3 फरवरी को ये शेयर बीएसई के SME

प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में प्राइस बैंड 61 से 64 रुपये प्रति शेयर रखा गया है, जबकि लॉट साइज 2,000 शेयर का है। रिटेल निवेशक अधिकतम दो लॉट यानी 4,000 शेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए 2,56,000 रुपये निवेश करने होंगे। इस इश्यू के तहत 27.52 लाख नए शेयर जारी किए जा रहे हैं। आईपीओ से पहले कंपनी ने चार प्रमुख एंकर निवेशकों से 5 करोड़ रुपये जुटाए, जिनमें एलआरएसडी

सिन्धोरिटीज, राजस्थान रोलबल सिन्धोरिटीज, टाडगर स्टेटेजिक फंड और इन्वोवेटिव विजन फंड शामिल हैं। इश्यू में क्यूआईबी के लिए 47.38 प्रतिशत, रिटेल निवेशकों के लिए 33.28 प्रतिशत, एनआईआई के लिए 14.32 प्रतिशत और मार्केट मेकर्स के लिए 5.01 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस प्रक्रिया के लिए हेम सिन्धोरिटीज बुक रनिंग लीड मैनेजर और बिगशेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार हैं।

## अडाणी-एम्ब्रेयर ने मिलाया हाथ, भारत में बनंगे यात्री विमान

दोनों कंपनियों ने नई दिल्ली में एमओयू पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। भारतीय विमानन विनिर्माण क्षेत्र को नई दिशा देते हुए अडाणी समूह और ब्राजील की वैश्विक एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर ने देश में क्षेत्रीय परिवहन विमानों के निर्माण की पहल की है। दोनों कंपनियों के बीच रणनीतिक सहयोग को लेकर मंगलवार को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। नागर विमानन मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और एम्ब्रेयर के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू की उपस्थिति में इस करार को औपचारिक रूप दिया।

## हवाई परिवहन तंत्र को मिलेगी मजबूती

इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत के क्षेत्रीय हवाई परिवहन तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'उड़ान' विजन से प्रेरित यह साझेदारी घरेलू विनिर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण सेवाओं को बढ़ावा देगी और 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी। इससे वैश्विक विमानन आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका और सुदृढ़ होगी।

## प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास भी शामिल

नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि यह सहयोग केवल विमानों के असेंबली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से भारत को क्षेत्रीय विमानों के एक भरोसेमंद विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के निदेशक जीत अडाणी ने कहा कि एम्ब्रेयर के साथ साझेदारी भारत में विमान निर्माण के क्षेत्र में समूह के प्रवेश को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि विनिर्माण इकाई के लिए संभावित स्थलों की पहचान की जा रही है और शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं, कंपनी के चेयरमैन एवं सीईओ आशीष राजनशी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गौरतलब है कि एम्ब्रेयर के ई-जेट विमानों का संचालन भारत में वर्ष 2005 से हो रहा है। वर्तमान में इसके लगभग 50 विमान भारतीय वायुसेना, सरकारी एजेंसियों और वाणिज्यिक विमानन कंपनियों की सेवाओं में हैं। एम्ब्रेयर 150 सीट तक की क्षमता वाले वाणिज्यिक विमानों के निर्माण में वैश्विक स्तर पर प्रमुख कंपनी मानी जाती है।



# दबदबा बरकरार रखने उतरेगी टीम इंडिया



► न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा टी-20 मुकाबला आज

एजेंसी | विशाखापत्तनम

टीम इंडिया पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुकी है। सूर्यकुमार एंड कंपनी बुधवार को चौथे टी-20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना दबदबा बरकरार रखने उतरेगी। भारतीय टीम किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहेगी। मैच में निगाह संजु सैमसन के साथ ही कुलदीप और चक्रवर्ती के प्रदर्शन पर रहेगी। कुलदीप और चक्रवर्ती अब तक फिरकी से कमाल नहीं दिखा पाए हैं। अगले महीने होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय टीम के पास अपनी कमियों को सुधारने के लिए इस मैच के बाद सिर्फ एक और मुकाबला बचा है। बल्लेबाजी में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम की चिंता स्पिनर बढ़ा रहे हैं। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप भी अब तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। वह प्रभावित करने में असफल रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने तीन महंगे ओवर किए जिनमें उन्होंने 32 रन दिए। वह वनडे सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। उन्होंने तीन मैचों में तीन विकेट लिए थे और प्रति ओवर 7.28 रन दिए थे। चक्रवर्ती को पिछले मैच में विश्राम दिया गया था। लेकिन पहले दो मैच में उनकी गेंदबाजी में वह धार नहीं दिखा जिसके लिए वह जाने जाते हैं।

बड़ी पारी खेलना चाहेंगे संजु

अगले महीने होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय टीम के पास अपनी कमियों को सुधारने के लिए इस मैच के बाद सिर्फ एक और मुकाबला बचा है। पहले मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो पिछले दो मैचों में अभिषेक, ईशान और कप्तान सूर्यकुमार ने शानदार प्रदर्शन कर एकतरफा जीत दिलाई। शीर्ष चार में सिर्फ संजु कमजोर कड़ी साबित हुए। वह तीन पारियों में एक बार दोहरा अंक तक पहुंचे हैं।

नंबर गेम

16 रन बना पाए हैं संजु सैमसन तीन मैचों में 5.33 की औसत से

9 प्रति ओवर लुटाए हैं चक्रवर्ती ने दो मैचों में और तीन विकेट झटके हैं

9.5 प्रति ओवर रन दिए हैं कुलदीप ने पिछले दो मैच में दो विकेट लि ले पाए हैं

सूर्य तीन हजारी बनने के करीब

कप्तान सूर्यकुमार तीन हजार रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बनने के करीब हैं। इसके लिए उन्हें 41 रन की जरूरत है। वह 102 मैचों में 165.03 की स्ट्राइक रेट और चार शतकों से 2959 रन बना चुके हैं।

सात साल से अजेय है भारत

भारतीय टीम डा. वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टैडियम में सात साल से अजेय है। उसे यहां पिछली और एकमात्र हार फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली थी। उसके बाद दो मुकाबले खेले और दोनों जीते। टीम ने कुल चार मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ एक हारा है।

आमने-सामने

कुल मैच : 28  
भारत जीता : 17  
न्यूजीलैंड जीता : 10  
टॉई : 1

अभिषेक, ईशान और सूर्य लय में

भारत ने दूसरे और तीसरे मैचों में क्रमशः 209 और 154 रन (कुल 363 रन) का पीछा करते हुए सिर्फ 25.2 ओवर ही खेले हैं। भारतीय बल्लेबाजी अभिषेक, ईशान और सूर्य के ईद-गिर्द ही रही। सूर्य ने 171 की औसत से रन बनाए हैं। निचले क्रम को हाथ खोलने का मौका नहीं मिला।

# अल्फाराज पहली बार सेमीफाइनल में

एजेंसी | मेलबर्न

दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्फाराज ने आखिरकार ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वार्टर फाइनल की बाधा पार कर ही ली। लगातार तीसरी बार अंतिम-8 में खेलने वाले अल्फाराज ने मंगलवार को स्थानीय खिलाड़ी और छठे वरीय एलेक्स डि मिनांस को 7-5, 6-2, 6-1 से हराकर शान के साथ पहली बार सेमीफाइनल का टिकट कटवाया। अल्फाराज 2024 में ज्येरेव और 2025 में जोकोविच से अंतिम-8 में हार गए थे। अब उनका सामना अब तीसरी वरीयता प्राप्त अलक्जेंडर ज्येरेव से होगा। जर्मनी ने ज्येरेव ने अमेरिका के 20 वरीय लर्नर टिएन को 6-3, 6-7, 6-1, 7-6 से हराया। ज्येरेव ने 24 ऐस लगाए और सिर्फ एक डबल फॉल्ट किया। वह मेलबर्न में चौथी और दसवीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम चार में पहुंचे।

नडाल-बोर्ग के क्लब में

अल्फाराज (22 साल 258 दिन) ने 23 साल की उम्र से दसवीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचकर दिगज बोर्ग, राफेल नडाल और बोरेस बेकर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। यही नहीं वह ओपन युग में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं।

ग्रैंड स्लैम से सिर्फ दो जीत दूर

अल्फाराज अब करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने से सिर्फ दो जीत दूर रह गए हैं। अगर वह रिवार को ट्रॉफी जीतने में सफल रहते हैं तो ओपन युग में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले छठे खिलाड़ी बन जाएंगे।



नंबर गेम

6 लगातार मुकाबलों में अल्फाराज ने मिर्नॉर को पराजित किया

8 वें स्पेशियल खिलाड़ी है मेलबर्न में अंतिम-चार में पहुंचने वाले

12 मैच दोनों ने अब तक खेले हैं जिसमें से छह ज्येरेव और इतने ही कार्लोस ने जीते हैं

स्वितोलिना ने कोको को किया बाहर, अब टक्कर सबालेंका से

साल की शुरुआत आकलेंड ओपन की ट्रॉफी के साथ करने वाली एलिना स्वितोलिना पहली बार यहां सेमीफाइनल में पहुंच गईं। यूक्रेन की 12वीं वरीयता प्राप्त स्वितोलिना ने मंगलवार को तीसरी वरीय कोको गफ को 59 मिनट में 6-1, 6-2 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फाइनल में जगह बनाने के लिए अब उन्हें दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी आर्यन सबालेंका की चुनौती से पार पाना होगा। भीषण गर्मी के कारण

मैच छत बंद करके खेले पड़े। ब्रेक के बाद वापसी करने वाली स्वितोलिना ने शुरू से ही दबदबा बना लिया जबकि गफ ने पहले सेट में पांच डबल फॉल्ट किए। अमेरिकी खिलाड़ी कोको ने इस बीच गुस्सा अपने रिकेट पर निकाला और उसे कई बार नीचे पटकता। स्वितोलिना ने मैच में सिर्फ तीन गेम गंवाए। मेलबर्न में तीसरे खिलाड़ी के लिए खेल रही बेलायूस की सबालेंका ने अमेरिका की 18 वरीय इवा जोविक को 6-3, 6-0 से हराया।

अपने पिता का सपना जी रहे अंबरीश

नई दिल्ली। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए मैच जिताने का प्रदर्शन करने वाले आरएस अंबरीश तेजी से चर्चा में आए हैं। 18 वर्षीय सीम गेंदबाजी ऑलराउंडर ने जिम्बाब्वे के बुलावावो में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट झटककर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ टीम को मजबूती दी, बल्कि अंबरीश को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में भी स्थापित किया। अंबरीश के इस प्रदर्शन को चेन्नई में बैठे उनके पिता आर. सुकुमार ने भावुक होकर देखा। सुकुमार खुद तमिलनाडु अंडर-19 टीम के कप्तान रह चुके हैं और रेलवे की घरेलू टीम तक पहुंचने के करीब थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। शनिवार को बेटे के 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के साथ सुकुमार का धूरा सपना एक तरह से पूरा हो गया।

अभी संन्यास लेने का इरादा नहीं : केएल राहुल

नई दिल्ली। भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने स्वीकार किया है कि उनके मन में संन्यास लेने का विचार आया था, लेकिन वह मानते हैं कि अभी इसमें कुछ समय बाकी है। उन्होंने साफ किया कि जब सही समय आएगा, तो वह इस फैसले को टालेंगे नहीं। राहुल गुरुवार को मोहाली में पंजाब के खिलाफ होने वाले रणजी मैच में कर्नाटक की ओर से खेलते नजर आएंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में राहुल ने कहा कि संन्यास लेना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल फैसला नहीं होगा। उनका मानना है कि क्रिकेट के अलावा भी जीवन है और अगर खिलाड़ी खुद के प्रति ईमानदार हो, तो सही समय पर पीछे हटने में संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वक्त आता है, तब बस चुपचाप खेल को अलविदा कह देना चाहिए और जो मिला है, उसका आनंद लेना चाहिए। राहुल ने कहा कि उनके लिए परिवार बेहद अहम है और पिता बनने के बाद जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है।



रानी के 30 साल और 'मर्दानी 3' की गूँज



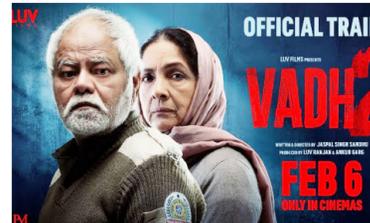
रणबीर कपूर का दिल छू लेने वाला रिएक्शन

रानी मुखर्जी के सिनेमा में 30 साल पूरे होने के जश्न के बीच अभिनेता रणबीर कपूर ने उनके लिए दिल से भरा संदेश शेर किया है। रणबीर ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि पूरा फिल्म उद्योग रानी की शानदार विरासत का जश्न मना रहा है, खासकर उनकी अपकमिंग फिल्म 'मर्दानी 3' के जरिए। रणबीर और रानी ने साथ में फिल्म 'सांवरिया' से काम किया था, जो रणबीर की डेब्यू फिल्म थी। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए रणबीर ने बताया कि रानी उन पहले लोगों में से थीं जिन्होंने उन पर भरोसा जताया। रणबीर ने कहा कि रानी ने उनसे कहा था कि अगर वह मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे और उस वक्त ये शब्द उनके लिए बेहद मायने रखते थे। उन्होंने रानी की शक्तिशाली और काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा है और हमेशा उनकी गरिमा,

आकर्षण और प्रतिभा से प्रभावित रहे हैं। रणबीर के मुताबिक, रानी उन कलाकारों में से हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उन्होंने यह भी माना कि रानी ने अपने किरदारों और फिल्मों के चुनाव से हिंदी सिनेमा में महिलाओं की प्रस्तुति को नई दिशा दी है। रणबीर ने रानी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी फिल्मों ने उन्हें ढेर सारी यादें और भावनाएं दी हैं। उनके मुताबिक, रानी ने हमेशा अपने सिनेमा के जरिए लोगों को खुशियां देने की कोशिश की है और एक एंटरटेनर के तौर पर उनका योगदान बेहद खास है। इसी बीच रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' भी चर्चा में बनी हुई है। यह फिल्म मर्दानी फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी है, जो हमेशा से महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मुद्दों को उठाती आई है। इस बार कहानी कम आय वर्ग से आने वाली छोटी बच्चियों के अपहरण जैसे संवेदनशील विषय पर केंद्रित होगी।

'वध 2' ट्रेलर रिलीज, थ्रिलर और ड्रामा का डबल डोज

रोमांटिक फिल्मों के लिए मशहूर निर्माता लव रंजन अब एक बार फिर गंभीर और रहस्यमयी कहानी के साथ दर्शकों के सामने आने वाले हैं। साल 2022 में आई फिल्म 'वध' को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद अब इसका सीक्वल 'वध 2' तैयार है, जो 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। रिलीज से पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसे दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। करीब 2 मिनट 21 सेकंड लंबे ट्रेलर में सस्पेंस, ड्रामा और रहस्यों की परतें एक साथ खुलती नजर आती हैं। इस बार कहानी एक मिस्सिंग केस के ईद-गिर्द घूमती है, जहां पुलिस की शक की हुई



शंभुनाथ (संजय मिश्रा) की ओर मुड़ती दिखाई देती है। ट्रेलर यह संकेत देता है कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होने वाली है, और हर किरदार अपने भीतर कोई न कोई राज छिपाए बैठा है।

दमदार स्टारकास्ट

जिएरि ही कहानी के टोन को गहरा और रहस्यमय बना दिया है। 'वध 2' एक बार फिर दर्शकों को नैतिक द्वंद, अपराध और इसानी भावनाओं की जटिल दुनिया में ले जाने के लिए तैयार दिख रही है।

विजय देवकोटा की 'वीडी 14' को मिला टाइटल 'राणा बाली'

पै न-इंडिया सुपरस्टार विजय देवकोटा एक बार फिर बड़े पर्दे पर दमदार वापसी के लिए तैयार हैं। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर मेकर्स ने उनकी अगली फिल्म 'वीडी 14' के टाइटल और रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का नाम 'राणा बाली' रखा गया है, जो एक भव्य ऐतिहासिक ड्रामा है। 'राणा बाली' किसी आम मसाला फिल्म से बिल्कुल अलग है। यह फिल्म 19वीं सदी के मध्य भारत में घटी सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है। निर्देशक राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने इससे पहले विजय देवकोटा के साथ सुपरहिट फिल्म 'टैक्सिवाला' बनाई थी, इस बार ब्रिटिश राज के दौर की क्रूरता और आर्थिक शोषण को बड़े पर्दे पर उतारने जा रहे हैं। फिल्म में ब्रिटिश अधिकारियों सर रिचर्ड टेम्पल और सर थियोडोर हेक्टर के दमनकारी नीतियों को दिखाया गया है, जिनकी वजह से देश के कई हिस्सों में भीषण सूखा और अकाल फैल गया था।

विजय-रश्मिका की हिट जोड़ी की वापसी

टीजर में इस ऐतिहासिक त्रासदी की तुलना हिटलर के 'होलोकॉस्ट' से भी ज्यादा भयावह बताई गई है। फैंस के लिए खास बात यह है कि फिल्म में विजय देवकोटा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर साथ नजर आएंगे। इससे पहले दोनों की जोड़ी 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' में दर्शकों का दिल जीत चुकी है। 'राणा बाली' इस हिट जोड़ी की तीसरी फिल्म होगी। फिल्म में विजय

देवकोटा 'राणा बाली' के किरदार में एक शक्तिशाली और उग्र अवतार में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना 'जयम्मा' का अहम रोल निभा रही हैं। वहीं, हॉलीवुड फिल्म 'द ममी' फेम अभिनेता आर्नोल्ड वॉल्सलू फिल्म में खूंखार घिलेन सर थियोडोर हेक्टर

11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक

'राणा बाली' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म विजय देवकोटा और माइश्री मूवी मेकर्स के बीच तीसरा सहयोग है। फिल्म को बड़े पैमाने पर और भारी बजट के साथ तैयार किया जा रहा है। संगीतकार अजय-अतुल का म्यूजिक और राहुल सांकृत्यायन का विजन इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव बनाने का दावा करता है।



# एसिड अटैक के मामलों में 'सुप्रीम' आदेश

एजेंसी। नई दिल्ली

देश में बढ़ते एसिड अटैक के मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे एसिड अटैक से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी अदालत को सौंपें। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसे केवल आंकड़े नहीं, बल्कि साल-दर-साल दर्ज मामलों, अदालती कार्रवाई की स्थिति और पीड़िताओं के पुनर्वास का पूरा व्यौरा चाहिए।

**राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों से मांगी विस्तृत जानकारी**

कुछ कानूनी दखल के बारे में सोचें... यह दहेज हत्या से कम गंभीर नहीं है।  
- सूर्यकांत, मुख्य न्यायाधीश

**जबरन एसिड पिलाने के मामलों पर विशेष चिंता**

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन जघन्य मामलों पर विशेष चिंता व्यक्त की, जिनमें पीड़ितों को जबरन एसिड पिलाया गया। अदालत ने ऐसे मामलों का अलग से पूरा विवरण मांगा है। यह देखा गया है कि एसिड पिलाने से आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे पीड़ित की स्थिति बाहरी हमलों की तुलना में और भी नाजुक और दर्दनाक हो जाती है।

**पीड़िताओं का सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल**

अदालत ने केवल कानूनी पहलुओं पर ही नहीं, बल्कि मानवीय पहलुओं पर भी जोर दिया है। कोर्ट ने हर पीड़ित से जुड़ी संक्षिप्त और व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। इसमें पीड़ित की शैक्षणिक योग्यता, उसका रोजगार, वैवाहिक स्थिति और हमले के बाद उनके जीवन पर पड़े प्रभाव का व्यौरा शामिल है। यह जानकारी पुनर्वास की रूपरेखा तय करने में मददगार साबित होगी।

**इलाज और पुनर्वास योजनाओं की समीक्षा**

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि एसिड अटैक पीड़ितों के लिए उनके यहां कौन-कौन सी पुनर्वास योजनाएं लागू हैं। इसके साथ ही, पीड़ितों के इलाज का पूरा विवरण, अब तक हुए खर्च और भविष्य में होने वाले संभावित खर्च की जानकारी भी मांगी गई है, ताकि उन्हें उचित आर्थिक मदद और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

**शाहीन मलिक की याचिका पर सुनवाई**

यह महत्वपूर्ण सुनवाई एसिड अटैक स्वर्दाय शाहीन मलिक द्वारा दायर जन्तित याचिका (PIL) पर हो रही थी। शाहीन मलिक ने अपनी याचिका में मांग की है कि 'दिव्यांगता' की कानूनी परिभाषा का दायरा बढ़ाया जाए। उनका तर्क है कि जिन पीड़ितों के आंतरिक अंग जबरन एसिड पिलाने से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी दिव्यांग माना जाए ताकि उन्हें उचित मुआवजा, इलाज और सरकारी राहत मिल सके।

# गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग

कानून मंत्री से मिले एन के पुरोहित



एजेंसी। नई दिल्ली

गौधम पथमेड़ा के आयोजन मंत्री एन के पुरोहित ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। एन के पुरोहित ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। उनका संरक्षण और सम्मान राष्ट्र के नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा विषय है।

**सरकार का सकारात्मक रुख**

मुलाकात के दौरान कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस विषय पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी कार्यकाल में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण, संवर्धन और इससे जुड़े सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशील है। केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने के प्रयासों में अपना पूर्ण योगदान देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन से जुड़े विषय राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना से जुड़े हैं और इस पर गंभीरता से कार्य किया जाना चाहिए।

**आश्वासन के लिए आभार जताया**

एन के पुरोहित ने इस आश्वासन के लिए कानून मंत्री का आभार जताया और कहा कि यह निर्णय देशभर में गौ भक्तों और सनातन परंपरा को मानने वालों की भावनाओं को सम्मान देगा। इस मुलाकात को गौ रक्षा आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

**न्यूज़ ग्रीफ**

**हीटवेव की चपेट में ऑस्ट्रेलिया, जनजीवन प्रभावित**

वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला। देश लंबे समय से जारी हीटवेव की चपेट में है और कई इलाकों में पारा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार से तापमान में कुछ गिरावट आने की उम्मीद है, हालांकि हीटवेव का असर सप्ताहांत तक बने रहने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रभावित विटोरीया की राजधानी मेलबर्न में होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट पर इसका असर साफ दिख रहा। आमतौर पर दर्शकों से खटाव भरे रहने वाले स्टेडियम परिसर के बाहर मंगलवार को सन्नाटा पसर रहा और तेज धूप के कारण भीड़ काफ़ी कम नजर आई। भीषण गर्मी को देखते हुए टूर्नामेंट आयोजकों को 'क्वार्टरमैन हीट प्रोटोकॉल' लागू करना पड़ा।

**केजरीवाल-आतिशी की याचिका पर सुनवाई स्थगित**

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की एक याचिका पर सुनवाई 21 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। याचिका में उन्होंने मतदाताओं के नाम हटाने संबंधी कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि मामला रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और एन. के. सिंह की पीठ ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी कि इसमें विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। आप नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने बताया कि पीठ ने कहा था कि इस मामले को नियमित मामलों की सुनवाई वाले दिन (मंगलवार, बुधवार और गुरुवार) को सुना जाना चाहिए। इसी आशय पर उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

**ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में छह हजार ज्यादा लोग मारे गए**

तेहरान। ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई में कम से कम 6,126 लोग मारे गए तथा कई और लोगों के मारे जाने की आशंका है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एंबेड्डेड न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी। यह समूह ईरान में मौजूद कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से मौत के प्रत्येक मामले की पुष्टि करता है और अतीत में इसके आंकड़े सही साबित हुए हैं। ईरान सरकार ने मृतकों की संख्या इससे कहीं कम 3,117 बताई है। उसने कहा है कि 2,427 लोग आम नागरिक और सुरक्षा बल थे, जबकि उसने शेष को आतंकवादी बताया। ईरान के धर्मतरंग ने पहले भी अशांति के दौरान मारे गए लोगों की संख्या कम बताई है या हताहतों की जानकारी नहीं दी है।

# 'महाकाल के सामने सब बराबर'

▶▶ महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन के खिलाफ याचिका खारिज

एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी दर्शन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक मामलों का नियमन न्यायिक दायरे में नहीं आता और ऐसे विषयों पर फैसला मंदिर प्रबंधन को ही करना चाहिए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस आर. महादेवन और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने दिया।



**हाईकोर्ट का फैसला बरकरार**

**मंदिर प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र पर जोर**

पीठ ने याचिकाकर्ता दर्शन अवस्था को इस मुद्दे पर मंदिर अर्थोपरी के समक्ष अपनी बात रखने की सलाह दी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मंदिर प्रबंधन में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं हैं और वीआईपी प्रवेश की अनुमति दी जाए नहीं, यह तय करना अदालत का काम नहीं है। यह निर्णय इन लोगों पर निर्भर करता है, जो मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

**याचिकाकर्ता के तर्क और वकील की दलील**

याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और संबंधित अधिकारियों के समक्ष पक्ष रखने की बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि वीआईपी दर्शन के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो एक सामान्य भक्त को भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का समान अधिकार मिलना चाहिए।

**मौलिक अधिकारों पर कोर्ट की चिंता**

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गर्भगृह के भीतर मौलिक अधिकारों को सख्ती से लागू करने से अनजाने परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार गंभीरता से लागू किया गया, तो आगे चलकर लोग अनुच्छेद 19 जैसे अन्य अधिकारों का भी दावा करने लगेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी यह कह चुका है कि वीआईपी की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है और यह मंदिर प्रबंधन समिति व कलेक्टर के प्रशासनिक विवेक का विषय है।

# जल्द होगी पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा



एजेंसी। नई दिल्ली

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का एक वीडियो माइगोव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया है, जिसे इस इवेंट का टेलर बताया जा रहा है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से सीधे संवाद करते नजर आ रहे हैं, जहां सवाल-जवाब के बीच हल्का-फुल्का माहौल और हंसी-मजाक भी देखने को मिला। वीडियो के अंत में संकेत दिया गया है कि पीएम मोदी जल्द ही परीक्षा पे चर्चा के तहत छात्रों से बातचीत करेंगे, हालांकि कार्यक्रम की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। परीक्षा पे चर्चा के लिए 1 दिसंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, जो 11 जनवरी 2026 तक चले। इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए और 4.5 करोड़ से अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया।

**इससे जुड़ी गतिविधियों में 6.76 करोड़ लोगों की भागीदारी**

# एआई से सुरक्षा चुनौतियों को पहले ही भांपने में सक्षम होंगे पुलिस बल

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रौद्योगिकी आधारित कानून प्रवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने पुलिस बलों में समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कम से कम 70 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को एआई के प्रयोगों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया है।



**करीब 70 फीसदी पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने की कवायद**

उच्च स्तरीय बैठकों में यह स्पष्ट किया गया कि आधुनिक पुलिसिंग में एआई का एकीकरण अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। गृह मंत्रालय खुफिया जानकारी जुटाने, वास्तविक समय में खतरों की पहचान और अपराध के पैटर्न व उभरते सुरक्षा जोखिमों के त्वरित विश्लेषण के लिए एक व्यापक एआई ढांचा विकसित करेगा।

**नेटग्रिड और एआई का एकीकरण**

इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नेटग्रिड) को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करना है। कई एजेंसियों से डेटा एकत्र करने वाला नेटग्रिड एआई-आधारित विश्लेषण के साथ और अधिक प्रभावी हो सकता है। 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में भी इस दिशा में तैयार ब्युट्रिट सामने आने की संभावना है।

# केरल सरकार केंद्र के नए लेबर कोड का करेगी विरोध



एजेंसी। तिरुवनंतपुरम

केरल के श्रम मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी करार दिया। विधानसभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नए लेबर कोड को रद्द कराने के लिए केंद्र पर हर संभव दबाव बनाएगी। उनका कहना था कि केरल सरकार श्रमिकों के हितों से समझौता नहीं करेगी। यह मुद्दा सीपीआई(एम) विधायक पी. नंदकुमार ने सदन में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नए नियम नौकरी की सुरक्षा को कमजोर करते हैं और वेतन से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करते हैं। इसके जवाब में मंत्री शिवनकुट्टी ने कहा कि मजदूरों के खिलाफ किसी भी कदम को केरल सरकार स्वीकार नहीं करेगी।

**मंत्री ने नीतियों को बताया मजदूर विरोधी**

**अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन सिंदूर पर झूठा और स्वार्थपूर्ण विवरण पेश करने पर दिया करारा जवाब**

# भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लगाई फटकार

एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठे और स्वार्थपूर्ण विवरणों का करारा जवाब दिया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तानी राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है, जिसे अब और सहन नहीं किया जाएगा।



**आतंकवाद को सामान्य बनाने की कोशिश नाकाम**

राजदूत हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा भारत और उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तानी राजदूत अहमद ने जब यह दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी प्रतिक्रिया ने 'दबाव की नई सामान्य स्थिति' को खारिज कर दिया है, तो भारत ने इसे सिरे से नकार दिया।

**जिम्मेदाराना और संतुलित सैन्य कार्रवाई**

राजदूत हरीश ने ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए बताया कि भारत की कार्रवाई पूरी तरह से संतुलित और जिम्मेदाराना थी। इसका उद्देश्य केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना और आतंकवादियों को निष्क्रिय करना था, न कि तनाव को बढ़ाना। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय मानकों और अपनी रक्षा के अधिकार के तहत हो।